



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 342]	नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 27, 2019/आश्विन 5, 1941
No. 342]	NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 27, 2019/ASVINA 5, 1941

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 27 सितम्बर, 2019

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (नगरपालिकाओं द्वारा ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) (संशोधन) विनियम, 2019

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/40.—भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (नगरपालिकाओं द्वारा ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,—

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (नगरपालिकाओं द्वारा ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) (संशोधन) विनियम, 2019 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त (लागू) होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (नगरपालिकाओं द्वारा ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2015 में,—

- (i) शीर्षक में, चिह्न तथा शब्द “(नगरपालिकाओं द्वारा ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता)”, चिह्नों तथा शब्दों “[म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों (म्युनिसिपल डैट सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता]” से प्रतिस्थापित हो जाएँगे।

- (II) आरंभिक पैरा में, शब्दों तथा चिह्नों “नगरपालिकाओं द्वारा ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़)” के लिए, शब्द तथा चिह्न, “म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों (म्युनिसिपल डैट सिक्यूरिटीज़)” प्रतिस्थापित हो जाएँगे।
- (III) विनियम 1 में, उप-विनियम (1) में, चिह्न तथा शब्द “(नगरपालिकाओं द्वारा ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता)”, चिह्नों तथा शब्दों “[म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों (म्युनिसिपल डैट सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता]” से प्रतिस्थापित हो जाएँगे।
- (IV) विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में, खंड (घ) से (थ) निम्नलिखित खंडों से प्रतिस्थापित हो जाएँगे, अर्थात्,-
- “ (घ) “गठन संबंधी दस्तावेज” से केंद्रीय या राज्य अधिनियम (एक्ट), नियम, विनियम (रेग्यूलेशन) या चार्टर अभिप्रेत होंगे, जिनके तहत निर्गमकर्ता (इश्युअर) को गठित या निगमित या अधिसूचित किया गया हो;
- (ङ) “क्रेडिट वृद्धि” (क्रेडिट एन्हांसमेंट) से कोई इंतजाम (अरेंजमेंट) अभिप्रेत होगा, जिसमें शामिल है - सबऑर्डिनेशन, बीमा, साख-पत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट), ओवर-कोलैटरलाइजेशन, वचन (अंडरटेकिंग), गारंटी, चुकौती आश्वासन पत्र (लेटर ऑफ कम्फर्ट), आदि;
- (च) “नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज” से वह मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज अभिप्रेत होगा, जहाँ निर्गमकर्ता (इश्युअर) की प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) सूचीबद्ध (लिस्टेड) हों या सूचीबद्ध किए जाने के लिए प्रस्तावित हों और जिसे निर्गमकर्ता द्वारा इन विनियमों के तहत म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़) के किसी निर्गम विशेष के प्रयोजनार्थ नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज के रूप में चुना जाता हो;
- (छ) “प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज” (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) से इन विनियमों के तहत सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) के संबंध में बोर्ड के पास दाखिल किया गया प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज अभिप्रेत होगा;
- (ज) “भगोड़ा आर्थिक अपराधी” से वह व्यक्ति अभिप्रेत होगा, जिसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, 2018) [2018 का 17] की धारा 12 के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया हो;
- (झ) “साधारण प्रयोजनों” में शामिल हैं - प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) या प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में निर्धारित किए गए ऐसे कोई प्रयोजन जिनके लिए कोई राशि आवंटित न की गई हो या साधारण प्रयोजन के लिए इस प्रकार निर्धारित की गई कोई रकम या ऐसा कोई प्रयोजन (चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए);
- (ञ) “ब्याज भुगतान खाता” (इंटेरेस्ट पेमेंट अकाउंट) से वह खाता अभिप्रेत होगा, जिसमें उधार लेने वाले / निर्गमकर्ता (इश्युअर) द्वारा अदा किए जाने वाले ब्याज की रकम जमा कराई जाए;
- (ट) “संस्थागत निवेशक” (इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर) का वही अर्थ होगा, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 के तहत इसके लिए नियत है;
- (ठ) “निर्गमकर्ता” (इश्युअर) से किसी केंद्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित या अधिसूचित कोई नगरपालिका या कोई सांविधिक निकाय (स्टैट्यूटरी बॉडी) या बोर्ड या निगम (कारपोरेशन), प्राधिकरण (अथॉरिटी), न्यास (ट्रस्ट) या एजेंसी अथवा राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कोई विशेष प्रयोजन माध्यम (स्पेशल पर्पज़ वीहिकल) अभिप्रेत होगा, बशर्ते कि वह ऐसा

कोई एक या एक से अधिक कार्य करता हो, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ब के तहत सौंपे जाएँ:

परंतु यह कि भारत सरकार की पूलड फाइनेंस डेवलपमेंट फंड स्कीम के तहत स्थापित कोई स्ट्रक्चर या ऐसा निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) जिस पर कंपनी अधिनियम, 2013 लागू होता हो, जो इन विनियमों के अनुसार म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियाँ (म्युनिसिपल डैट सिक्यूरिटीज़) लाता हो या लाने का प्रस्ताव करता हो, को भी निर्गमकर्ता (इश्युअर) समझा जाएगा, बशर्ते कि वह राज्य सरकार (सरकारों) या केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसे व्यक्ति के लिए निधियाँ (पैसे/फंड) जुटाने के प्रयोजन से गठित किया गया हो, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ब के तहत सौंपा गया कोई एक या एक से अधिक कार्य करता हो।

(ड) "म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों" (म्युनिसिपल डैट सिक्यूरिटीज़) से ऐसी असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियाँ (नॉन-कन्वर्टिबल डैट सिक्यूरिटीज़) अभिप्रेत होंगी, जिनके कारण ऋणग्रस्तता सृजित हो जाती हो या जिनके जरिए ऋणग्रस्तता स्वीकार की जाती हो, और जिनमें शामिल हैं – निर्गमकर्ता का डिबेंचर, बॉण्ड तथा ऐसी अन्य प्रतिभूतियाँ;

(ढ) "नगरपालिका" से भारत के संविधान के अनुच्छेद 243थ के तहत गठित स्वायत्त शासन की कोई संस्था अभिप्रेत होगी;

(ण) "नेशनल म्युनिसिपल अकाउंट्स मैनुअल" से केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर बनाया जाने वाला म्युनिसिपल अकाउंटिंग मैनुअल अभिप्रेत होगा;

(त) "धारणाधिकार रहित निलंब खाते" (नो लियन एस्करो अकाउंट) से संविदात्मक बाध्यताओं का निर्वहन करने हेतु पैसा (निधियाँ/फंड) प्राप्त करने और वितरित करने के प्रयोजन विशेष हेतु बनाया गया खाता अभिप्रेत होगा;

(थ) "प्रस्ताव दस्तावेज" (ऑफर डॉक्यूमेंट) से कोई ऐसा दस्तावेज अभिप्रेत होगा, जिसमें शामिल है – प्रस्ताव दस्तावेज या प्रॉस्पेक्टस या शेल्फ प्रस्ताव दस्तावेज के रूप में उल्लिखित या जारी किया गया इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, और जिसमें कोई ऐसा दस्तावेज या विज्ञापन शामिल होगा, जिसके माध्यम से निर्गमकर्ता (इश्युअर) द्वारा म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों में अभिदान करने (पैसा लगाने / सब्सक्रिप्शन करने) के लिए जनता को आमंत्रित किया जाता हो;

(द) "स्थानन ज्ञापन" (प्लेसमेंट मैमोरेन्डम) से कोई ऐसा दस्तावेज अभिप्रेत होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज शामिल है, जिसे क्रमानुसार संख्यांकित किया गया हो और जिनकी प्रतियाँ केवल चुनिंदा निवेशकों को परिचालित की गई हों और जो निजी स्थानन (प्राइवेट प्लेसमेंट) आधार पर लाए गए निर्गम (इश्यू) से संबंधित हो;

(ध) "निजी स्थानन" (प्राइवेट प्लेसमेंट) से म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों (म्युनिसिपल डैट सिक्यूरिटीज़) का कोई प्रस्ताव (ऑफर) या म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों में अभिदान करने (पैसा लगाने / सब्सक्राइब करने) के लिए कोई आमंत्रण अभिप्रेत होगा, जो निर्गमकर्ता (इश्युअर) द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम दो सौ व्यक्तियों को स्थानन ज्ञापन (प्लेसमेंट मैमोरेन्डम) जारी करके चुनिंदा व्यक्तियों के वर्ग के लिए लाया जाए या को दिया जाए, जिसका आशय यह न हो कि उससे, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियाँ उन व्यक्तियों से भिन्न व्यक्तियों द्वारा पैसा लगाए जाने हेतु (अभिदान / सब्सक्रिप्शन हेतु) या खरीदे जाने हेतु उपलब्ध हो जाएँ, जिन्हें प्रस्ताव (ऑफर) या आमंत्रण प्राप्त हुआ हो:

परंतु यह कि,-

- i. जिस निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) पर कंपनी अधिनियम, 2013 लागू होता हो, उस निगमित निकाय हेतु, इससे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, स्थानन ज्ञापन (प्लेसमेंट मैमोरेन्डम) जारी करके लाया जाने वाला प्रस्ताव या दिया जाने वाला आमंत्रण अभिप्रेत होगा;
- ii. अर्हित संस्थागत क्रेताओं (क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशनल बायर्स) के लिए लाए गए किसी प्रस्ताव या को दिए गए किसी आमंत्रण पर दो सौ व्यक्तियों की गणना करते समय विचार नहीं किया जाएगा;

(न) "प्रारंभिक स्थानन ज्ञापन" (प्लेसमेंट मैमोरेन्डम) से इन विनियमों के तहत निजी स्थानन (प्राइवेट प्लेसमेंट) के संबंध में बोर्ड तथा स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के पास दाखिल किया जाने वाला स्थानन ज्ञापन (प्लेसमेंट मैमोरेन्डम) अभिप्रेत होगा;

(प) "सार्वजनिक निर्गम" (पब्लिक इश्यू) से निर्गमकर्ता (इश्युअर) द्वारा म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों (म्युनिसिपल डैट सिक्यूरिटीज़) में पैसा लगाने (अभिदान / को सब्सक्राइब करने) हेतु जनता के लिए लाया जाने वाला प्रस्ताव या को दिया जाने वाला आमंत्रण अभिप्रेत होगा, जो निजी स्थानन (प्राइवेट प्लेसमेंट) के स्वरूप का न हो;

(फ) "अर्हित संस्थागत क्रेता" (क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशनल बायर) का वही अर्थ होगा जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 के तहत इसके लिए नियत है;

(ब) "अनुसूची" से इन विनियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत होगी;

(भ) "शेल्फ प्रस्ताव दस्तावेज" से ऐसा प्रस्ताव दस्तावेज अभिप्रेत होगा, जिसके संबंध में उस शेल्फ प्रस्ताव दस्तावेज में उल्लिखित म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों का प्रस्ताव, उस प्रस्ताव दस्तावेज के तहत प्रतिभूतियों के पहले प्रस्ताव के खुलने की तारीख से एक वर्ष तक की अवधि के दौरान एक या एक से अधिक प्रस्तावों के माध्यम से [कोई बाद वाला प्रस्ताव दस्तावेज (फर्दर ऑफर डॉक्यूमेंट) जारी किए बिना] पैसा लगाने (अभिदान करने / सब्सक्रिप्शन) हेतु जनता के लिए लाया जाता हो;

परंतु यह कि जिस निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) पर कंपनी अधिनियम, 2013 लागू होता हो, उस निगमित निकाय हेतु, इसका वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 31 में "शेल्फ प्रॉस्पेक्टस" के लिए नियत है;

(म) "सिंकिंग फंड खाते" से वह खाता अभिप्रेत होगा, जिसे विशेष रूप से म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों (म्युनिसिपल डैट सिक्यूरिटीज़) की चुकौती के लिए बनाया गया हो;

(य) "निर्धारित" में शामिल है – बोर्ड द्वारा जारी विनियमों (रेग्यूलेशन्स) द्वारा अथवा साधारण या विशेष आदेश या परिपत्र (सर्कुलर) द्वारा निर्धारित;

(यक) "इरादतन चूककर्ता" (जानबूझकर चूक करने वाला) से वह व्यक्ति या निर्गमकर्ता (इश्युअर) अभिप्रेत होगा, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इरादतन चूककर्ताओं के संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देशों (गाइडलाइन्स / मार्गदर्शक सिद्धांत) के अनुसार, किसी बैंक या वित्तीय संस्था (कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत यथा परिभाषित) या उनके कनसॉर्टियम द्वारा, इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया हो।"

- (V) विनियम 2 में, उप-विनियम (2) में, शब्दों, चिह्न तथा अंकों “या कंपनी अधिनियम, 2013” का लोप हो जाएगा ।
- (VI) विनियम 3 में, खंड (क) एवं (ख) निम्नलिखित खंडों से प्रतिस्थापित हो जाएँगे, अर्थात्,-
- “(क) सार्वजनिक निर्गमन (पब्लिक इश्युएंस) के माध्यम से निर्गमकर्ता (इश्युअर) द्वारा म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों के निर्गमन और उनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग) के प्रति लागू होंगे; और
- (ख) निजी स्थानन (प्राइवेट प्लेसमेंट) आधार पर निर्गमकर्ता (इश्युअर) द्वारा ऐसी म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों के निर्गमन और उनकी सूचीबद्धता के प्रति लागू होंगे, जिन्हें मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराए जाने का इरादा हो / सूचीबद्ध कराए जाने के संबंध में प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) किया गया हो ।”
- (VII) अध्याय-II में, अध्याय के शीर्षक में, शब्द “पात्रता” के पश्चात्, शब्द “और शर्तें” अंतःस्थापित किए जाएँगे ।
- (VIII) अध्याय-II में,-
- (i) विनियम 4 से पूर्व, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“संदर्भ तारीख

3क. जब तक कि इन विनियमों में अन्यथा प्रावधान न किया गया हो, म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों का प्रस्ताव लाने वाला निर्गमकर्ता (इश्युअर), यथास्थिति, बोर्ड के पास प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) या आरंभिक स्थानन ज्ञापन (प्लेसमेंट मैमोरेन्डम) दाखिल किए जाने की तारीख तक और बोर्ड के पास प्रस्ताव दस्तावेज या स्थानन ज्ञापन (प्लेसमेंट मैमोरेन्डम) दाखिल किए जाने की तारीख तक भी या कंपनी रजिस्ट्रार के पास प्रस्ताव दस्तावेज या स्थानन ज्ञापन (प्लेसमेंट मैमोरेन्डम) रजिस्टर किए जाने के समय इन विनियमों में दी हुई शर्तों को पूरा करेगा ।”

- (ii) विनियम 4 निम्नलिखित विनियम से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“पात्र निर्गमकर्ता (इश्युअर्स)

4. कोई भी निर्गमकर्ता (इश्युअर) तब तक इन विनियमों के अधीन म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियाँ निर्गमित (इश्यू) करने का पात्र नहीं होगा, जब तक कि निम्नलिखित मानदंडों का पालन न कर लिया जाए:

(क) म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियाँ निर्गमित (इश्यू) करने का प्रस्ताव करने वाला निर्गमकर्ता अपने गठन संबंधी दस्तावेज के तहत पैसे (निधियाँ / फंड) जुटाने का पात्र है;

(ख) निर्गमकर्ता के लेखे (अकाउंट्स) निम्नलिखित में से किसी एक के अनुसार तैयार किए जाएँगे :

- i. नेशनल म्युनिसिपल अकाउंट्स मैनुअल के अनुसार; या
- ii. संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपनाए गए म्युनिसिपल अकाउंट्स मैनुअल के अनुसार; या
- iii. निर्गमकर्ताओं (इश्युअर) पर लागू लेखा मानकों (अकाउंटिंग स्टैंडर्ड) [कंपनी अधिनियम के तहत यथा निर्धारित] के अनुसार; या
- iv. निर्गमकर्ताओं पर लागू लेखा मानकों / नीतियों [जिनका उल्लेख उनके गठन संबंधी दस्तावेज में किया गया हो] के अनुसार ।

- (ग) निर्गमकर्ता ने, पिछले तीन सौ पैसठ दिनों के दौरान, ऋण प्रतिभूतियों (डेट सिक्यूरिटीज़) की अथवा बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से लिए गए उधारों की चुकौती (रीपेमेंट) करने में चूक न की हो;
- (घ) बोर्ड द्वारा प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में पहुँच रखने से अवरुद्ध किए जाने, प्रतिषिद्ध किए जाने या विवर्जित किए जाने के संबंध में निर्गमकर्ता (इश्युअर) या उसके संप्रवर्तकों (प्रमोटर) या उसके निदेशकों के खिलाफ जारी किया गया कोई भी आदेश या निदेश प्रवृत्त न हो;
- (ङ) निर्गमकर्ता (इश्युअर) या उसके संप्रवर्तक (प्रमोटर), उसकी समूह (ग्रुप) कंपनी या उसके निदेशक (निदेशकों) का नाम इरादतन चूककर्ताओं (जानबूझकर चूक करने वालों) की सूची में न आया हो;
- (च) उसके किसी संप्रवर्तक (प्रमोटर) या निदेशक को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित न किया गया हो:

परंतु यह कि जहाँ निर्गमकर्ता (इश्युअर) एक निगमित निकाय (बाँडी कारपोरेट) हो जिस पर कंपनी अधिनियम, 2013 लागू होता हो, या एक विशेष प्रयोजन माध्यम (स्पेशल पर्पज़ वीहिकल) हो, जिसे ऐसे व्यक्ति के लिए पैसे (निधियाँ/फंड) जुटाने के प्रयोजन से गठित किया गया हो जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ब के तहत सौंपे गए एक या एक से अधिक कार्य करता हो, तो ऊपर खंड (ख) एवं (ग) में दी हुई अपेक्षाओं का पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसका वित्तपोषण (फाइनेंसिंग) किया जा रहा हो;

- (iii) विनियम 4 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्,-

“सैद्धांतिक मंजूरी

4क. निर्गमकर्ता (इश्युअर) एक या एक से अधिक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में ऐसी प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता (लिस्टिंग) के लिए उनके पास आवेदन करेगा:

परंतु यह कि जहाँ आवेदन एक से अधिक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को किया जाए, वहाँ निर्गमकर्ता (इश्युअर) उनमें से किसी एक को नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज के रूप में चुनेगा:

स्पष्टीकरण – बाद में लाए जाने वाले किसी निर्गम (इश्यू) के लिए, निर्गमकर्ता (इश्युअर), इन विनियमों की अपेक्षाओं के अध्वधीन किसी दूसरे स्टॉक एक्सचेंज को नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज के रूप में चुन सकेगा।

साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग)

4ख. निर्गमकर्ता (इश्युअर) बोर्ड से रजिस्ट्रीकृत कम से कम एक साख निर्धारण एजेंसी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसी) से क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करेगा, जिसका प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) या स्थानन ज्ञापन (प्लेसमेंट मेमोरैन्डम) [जो भी लागू हो] में किया जाएगा:

परंतु यह कि जहाँ क्रेडिट रेटिंग एक से अधिक साख निर्धारण एजेंसियों (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों) से प्राप्त की जाए, वहाँ सभी रेटिंगें (जिनमें वे रेटिंगें भी शामिल हैं, जिन्हें स्वीकार न किया गया हो) प्रस्ताव दस्तावेज या स्थानन ज्ञापन, जो भी लागू हो, में प्रकट की जाएँगी।

डीमैट रूप में रखना

4ग. निर्गमकर्ता, म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों, जिन्हें निर्गमित (इश्यू) किए जाने के का प्रस्ताव हो, को डीमैट रूप में रखने के लिए, निक्षेपागार अधिनियम, 1996 [डिपॉज़िटरीज़ एक्ट,

1996] तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार, बोर्ड से रजिस्ट्रीकृत निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) के साथ करार करेगा।

डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर ट्रस्टी)

4घ. निर्गमकर्ता (इश्युअर), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993 के प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड से रजिस्ट्रीकृत डिबेंचर न्यासी को नियुक्त करेगा।

अनिवार्य सूचीबद्धता (लिस्टिंग)

4ङ. (1) निर्गमकर्ता (इश्युअर), एक या एक से अधिक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के पास सूचीबद्धता (लिस्टिंग) के लिए उसी प्रकार आवेदन करेगा, जैसा बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया हो।

(2) यदि निर्गमकर्ता (इश्युअर) उन मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों [जहाँ म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध (लिस्टिड) कराए जाने का प्रस्ताव था] में से किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से, सूचीबद्धता (लिस्टिंग) तथा व्यापार (ट्रेडिंग) के संबंध में अनुमति प्राप्त करने में असफल रहता हो, तो वह म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता हेतु किए गए आवेदन को नामंजूर किए जाने के संबंध में स्टॉक एक्सचेंज से सूचना प्राप्त होने की तारीख से सात दिनों के भीतर या एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंजों के मामले में सबसे पहली बार सूचना प्राप्त होने की तारीख से सात दिनों के भीतर, प्राप्त हुई पूरी रकम लौटा देगा (रिफंड कर देगा), और यदि ऐसी कोई रकम, पैसा लौटाए जाने के संबंध में निर्गमकर्ता के दायी हो जाने के बाद भी नहीं लौटाई जाती, तो निर्गमकर्ता तब तक पंद्रह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के साथ वह रकम लौटाने का दायी होगा, जब तक कि ऐसी रकम लौटा न दी जाए।

परंतु यह कि जहाँ निर्गमकर्ता एक निगमित निकाय हो जिस पर कंपनी अधिनियम, 2013 लागू होता हो, वहाँ कंपनी का ऐसा प्रत्येक निदेशक जो चूककर्ता अधिकारी हो, संयुक्त रूप से और पृथक् रूप से, ब्याज के साथ वह रकम लौटाने का दायी होगा।”

(IX) अध्याय-III में,-

(i) विनियम 5, निम्नलिखित विनियम से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) हेतु पात्रता संबंधी शर्तें

5. कोई भी निर्गमकर्ता (इश्युअर) म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों का सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) तब तक नहीं लाएगा, जब तक कि निम्नलिखित शर्तों का पालन न कर लिया जाए:

(क) निर्गमकर्ता की, ठीक पहले के तीन वित्तीय वर्षों में से किसी वित्तीय वर्ष में उसके आय-व्यय संबंधी विवरण के अनुसार या किसी अन्य वित्तीय मानदंड, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाएँ, के अनुसार अधिशेष आय हो:

परंतु यह कि जहाँ निर्गमकर्ता एक निगमित निकाय हो जिस पर कंपनी अधिनियम, 2013 लागू होता हो, वहाँ ठीक पहले के तीन वित्तीय वर्षों में से किसी वित्तीय वर्ष में उसकी शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) ऋणात्मक (नेगेटिव) न रही हो:

परंतु यह कि जहाँ निर्गमकर्ता (इश्युअर) एक निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) हो जिस पर कंपनी अधिनियम, 2013 लागू होता हो, या एक विशेष प्रयोजन माध्यम (स्पेशल पर्पज़ वीहिकल) हो, जिसे ऐसे व्यक्ति के लिए पैसे (निधियाँ/फंड) जुटाने के प्रयोजन से गठित किया गया हो जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ब के तहत सौंपे गए एक या

एक से अधिक कार्य करता हो, तो ऊपर खंड (क) में दी हुई अपेक्षाओं का पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसका वित्तपोषण (फाइनेंसिंग) किया जा रहा हो;

(ख) कोई अन्य शर्तें, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएँ।”

(ii) विनियम 6, निम्नलिखित विनियम से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -

“प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज तथा प्रस्ताव दस्तावेज में प्रकटीकरण

6. (1) प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) तथा प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में सही, उचित और महत्वपूर्ण (तात्विक) प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र्स) शामिल होंगे, जो म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों के अभिदाताओं (पैसा लगाने वालों / सब्सक्राइबर्स) के लिए निवेश के संबंध में सोच-समझकर निर्णय लेने के लिए आवश्यक हों।

(2) उप-विनियम (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निर्गमकर्ता (इश्युअर) और अग्रणी प्रबंधक (लीड मैनेजर) यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज में निम्नलिखित शामिल हो:

(क) इन विनियमों की अनुसूची-1 एवं अनुसूची-1क में निर्धारित प्रकटीकरण;

(ख) अतिरिक्त प्रकटीकरण, जो बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जाएँ:

परंतु यह कि जहाँ निर्गमकर्ता (इश्युअर) एक निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) हो जिस पर कंपनी अधिनियम, 2013 लागू होता हो, वहाँ निर्गमकर्ता और अग्रणी प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) तथा प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में वे प्रकटीकरण भी शामिल हों जो कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी (प्रॉस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आबंटन) नियम, 2014 [कंपनीज़ (प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ़ सिक्यूरिटीज़) रूल्स, 2014] के अनुसार अनिवार्य हों।

(3) अग्रणी प्रबंधक पूरी तत्परता बरतेगा (बरतेंगे) और निर्गम (इश्यू) के समस्त पहलुओं के मद्देनज़र अपनी संतुष्टि कर लेगा (लेंगे), जिनके अंतर्गत प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज और प्रस्ताव दस्तावेज में किए गए प्रकटीकरणों की सत्यता और पर्याप्तता शामिल है।”

(iii) विनियम 6 के पश्चात् और विनियम 7 से पूर्व, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

“मर्चेन्ट बैंककार (बैंकर) तथा अन्य मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) की नियुक्ति

6क. (1) निर्गमकर्ता (इश्युअर) बोर्ड से रजिस्ट्रीकृत एक या एक से अधिक मर्चेन्ट बैंककारों (बैंकर्स) को, निर्गम (इश्यू) के अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों) [लीड मैनेजर] के रूप में, नियुक्त करेगा।

(2) जहाँ निर्गम (इश्यू) का कामकाज एक से अधिक अग्रणी प्रबंधकों द्वारा देखा जाता हो, वहाँ, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रकटीकरणों (डिस्क्लोज़र्स), आबंटन (अलॉटमेंट), पैसा लौटाए जाने (रिफंड) तथा हामीदारी (अंडरराइटिंग) संबंधी बाध्यताओं, यदि कोई हों, से संबंधित प्रत्येक अग्रणी प्रबंधक के अधिकारों, उसकी बाध्यताओं तथा जिम्मेदारियों को पहले ही तय कर लिया जाएगा, और जिन्हें प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज तथा प्रस्ताव दस्तावेज में प्रकट किया जाएगा।

(3) निर्गमकर्ता, अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों) द्वारा अन्य मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) की वाध्यताओं को निभाने की क्षमता का स्वतंत्र रूप से आकलन करने के बाद, अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों) के परामर्श से, अन्य रजिस्ट्रीकृत मध्यवर्तियों को नियुक्त करेगा।

(4) जहाँ केवल एक ही अग्रणी प्रबंधक हो, वहाँ वह निर्गमकर्ता (इश्युअर) का सहयोगी (सहयुक्त/असोसिएट) [भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंककार) विनियम, 1992 के तहत परिभाषित है] नहीं होगा।

(5) यदि एक से अधिक अग्रणी प्रबंधक (लीड मैनेजर) हों, तो निर्गम (इश्यू) का कम से कम एक अग्रणी प्रबंधक निर्गमकर्ता का सहयोगी (सहयुक्त/असोसिएट) [जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंककार) विनियम, 1992 के तहत परिभाषित है] नहीं होगा।

(6) यदि अग्रणी प्रबंधक निर्गमकर्ता का सहयोगी हो, तो वह स्वयं को निर्गमकर्ता के सहयोगी के रूप में प्रकट करेगा और उसकी भूमिका निर्गम की मार्केटिंग (के विपणन) तक ही सीमित रहेगी।”

(iv) विनियम 7, निम्नलिखित विनियम से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल करना

7. (1) कोई भी निर्गमकर्ता (इश्युअर) म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों (डेट सिक्यूरिटीज़) का सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) तब तक नहीं लाएगा, जब तक कि अग्रणी प्रबंधक (लीड मैनेजर) के माध्यम से बोर्ड तथा नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज के पास प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) दाखिल न कर दिया जाए:

परंतु यह कि जहाँ निर्गमकर्ता ने शेल्फ प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल किया हो, वहाँ एक शेल्फ प्रस्ताव दस्तावेज के माध्यम से अधिकतम चार सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) लाए जा सकेंगे।

(2) अग्रणी प्रबंधक प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज के साथ बोर्ड को निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा,-

(क) प्रमाणपत्र, जिसमें यह पुष्टि की जाए कि निर्गमकर्ता और अग्रणी प्रबंधक के बीच लिखित करार (एग्रीमेंट) कर लिया गया है;

(ख) अनुसूची-II के फॉर्म-क के अनुसार पूरी तत्परता बरते जाने संबंधी प्रमाणपत्र (ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट)।

(3) बोर्ड, निम्नलिखित तारीखों में से जो अंतिम तारीख हो उस तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर, प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज के संबंध में परिवर्तनों का उल्लेख कर सकेगा या अभिमत जारी कर सकेगा, यदि कोई हों:

(क) उप-विनियम (1) के तहत प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज के प्राप्त होने की तारीख; या

(ख) अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों) से संतोषजनक उत्तर के प्राप्त होने की तारीख, जहाँ बोर्ड ने उनसे कोई स्पष्टीकरण मांगा हो या अतिरिक्त जानकारी मांगी हो; या

(ग) किसी विनियामक (रेग्युलेटर) या एजेंसी से स्पष्टीकरण या जानकारी के प्राप्त होने की तारीख, जहाँ बोर्ड ने ऐसे विनियामक (रेग्युलेटर) या एजेंसी से कोई स्पष्टीकरण मांगा हो या जानकारी मांगी हो; या

(घ) स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी हेतु जारी किए गए पत्र की प्रति के प्राप्त होने की तारीख।

(4) नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल किए गए प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज को नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पर डालकर सार्वजनिक किया जाएगा, ताकि ऐसे एक्सचेंज के पास प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल किए जाने की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि तक जनता की टिप्पणियाँ मांगी जा सकें और वह डाउनलोड करने के लिए पीडीएफ/एचटीएमएल फॉर्मेट में उपलब्ध रहेगा।

(5) प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज को निर्गमकर्ता, अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों) और उन स्टॉक एक्सचेंजों के वेबसाइटों पर भी प्रदर्शित किया जाएगा, जहाँ म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध कराए जाने का प्रस्ताव हो।

(6) अग्रणी प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज में निर्गमकर्ता के अग्रणी प्रबंधक के अनुपालन अधिकारी (कम्प्लायन्स ऑफिसर), संबंधित अधिकारी और परियोजना अधिकारी (प्रोजेक्ट ऑफिसर), जहाँ कहीं भी लागू हो, के नाम और संपर्क संबंधी ब्यौरे दिए हुए हों जिनमें उनका डाक और ई-मेल का पता, दूरभाष और फैक्स संख्याएँ शामिल हैं।

(7) अग्रणी प्रबंधक, उप-विनियम (4) में उल्लिखित अवधि के समाप्त होने के पश्चात्, उप-विनियम (4) में उल्लिखित अवधि के दौरान प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज के संबंध में उनके द्वारा या निर्गमकर्ता द्वारा जनता से प्राप्त टिप्पणियों तथा उनके मद्देनज़र बाद में किए गए बदलावों, यदि कोई हों, के ब्यौरे बोर्ड के पास प्रस्तुत करेगा, जो तदनुसार प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज में किए जाने अपेक्षित हों।

(8) यदि बोर्ड किन्हीं परिवर्तनों का उल्लेख करता है या कोई अभिमत (ऑब्ज़र्वेशन) जारी करता है, तो निर्गमकर्ता तथा अग्रणी प्रबंधक प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज में ऐसे परिवर्तन करेगा (करेंगे) और बोर्ड द्वारा जारी किए गए अभिमतों का पालन करके अपडेट किया हुआ प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (जिसमें प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज में किए गए सभी परिवर्तनों को हाइलाइट करके दर्शाया गया हो), बोर्ड के पास, यथास्थिति, स्टॉक एक्सचेंज या कंपनी रजिस्ट्रार के पास प्रस्ताव दस्तावेज को दाखिल करने से पहले, प्रस्तुत करेंगे।

(9) अग्रणी प्रबंधक बोर्ड द्वारा अभिमत जारी किए जाने के पश्चात् या यदि बोर्ड ने अभिमत जारी न किए हों तो इस विनियम के उप-विनियम (3) में उल्लिखित अवधि की समाप्ति के पश्चात्, बोर्ड को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा (करेंगे):

(क) यह प्रमाणित करते हुए कथन कि बोर्ड द्वारा किए गए सभी परिवर्तनों, दिए गए सभी सुझावों तथा जारी किए गए अभिमतों को प्रस्ताव दस्तावेज या स्थानन जापन (प्लेसमेंट मैमोरेन्डम) में शामिल कर लिया गया है;

(ख) अनुसूची-II के फॉर्म-ख एवं फॉर्म-ग के अनुसार पूरी तत्परता बरते जाने (ड्यू डिलीजेंस) संबंधी प्रमाणपत्र।

(10) प्रारूप और अंतिम प्रस्ताव दस्तावेज की प्रति (सॉफ्ट कॉपी के साथ) नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल करने के साथ-साथ बोर्ड को भी भेजी जाएगी।

(11) शेल्फ प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल करने वाला निर्गमकर्ता (इश्युअर) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों और बोर्ड के पास सूचना जापन (इन्फॉर्मेशन मैमोरेन्डम) की प्रति भी दाखिल करेगा, जिसमें सभी महत्वपूर्ण तथ्य (जैसे म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों के पिछले प्रस्ताव या पहले प्रस्ताव या बाद के प्रस्ताव के दौरान वित्तीय स्थिति में जो भी परिवर्तन हुए हों) शामिल हों, और

यदि निर्गमकर्ता ऐसा निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) हो जिस पर कंपनी अधिनियम, 2013 लागू होता हो, तो ऐसा निर्गमकर्ता उसकी प्रति कंपनी रजिस्ट्रार के पास भी दाखिल करेगा।

(12) अग्रणी प्रबंधक, सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) के खुलने से पहले, बोर्ड को प्रस्ताव दस्तावेज के साथ इन विनियमों की अनुसूची-II के अनुसार पूरी तत्परता बरती जाने संबंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा:

परंतु यह कि जहाँ निर्गमकर्ता ऐसा निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) हो जिस पर कंपनी अधिनियम, 2013 लागू होता हो, वहाँ अग्रणी प्रबंधक, कंपनी रजिस्ट्रार के पास अंतिम प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल करने से पूर्व, बोर्ड के पास इन विनियमों की अनुसूची-II के अनुसार पूरी तत्परता बरती जाने संबंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

(13) डिबेंचर न्यासी, सार्वजनिक निर्गम के खुलने से पूर्व, बोर्ड के पास इन विनियमों की अनुसूची-III के अनुसार पूरी तत्परता बरते जाने संबंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

(14) निर्गमकर्ता और अग्रणी प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्ताव दस्तावेज वेबसाइटों पर डाल दिए जाएँ, जैसा कि इन विनियमों के तहत अपेक्षित है, और उनकी विषय-वस्तु वही हो जो कंपनी रजिस्ट्रार, बोर्ड तथा स्टॉक एक्सचेंजों (जो भी लागू हो) के पास दाखिल किए गए प्रस्ताव दस्तावेजों में हो।

(15) जब कभी अनुरोध किया जाए, तब अग्रणी प्रबंधक और स्टॉक एक्सचेंज जनता को प्रस्ताव दस्तावेज की प्रतियाँ उपलब्ध कराएँगे और इसकी प्रति उपलब्ध कराने के लिए वे उपयुक्त शुल्क ले सकेंगे।”

(v) विनियम 8, निम्नलिखित विनियम से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,—

“अभिधान की अवधि

8. (1) जब तक कि इन विनियमों में अन्यथा प्रावधान न किया गया हो, म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों का सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) कम से कम तीन कार्य-दिवसों के लिए खुला रखा जाएगा।

(2) अनिवार्य बाध्यता, बैंक हड़ताल या ऐसी ही अन्य परिस्थितियों में, निर्गमकर्ता प्रस्ताव दस्तावेज में प्रकट की गई बोली की अवधि कम से कम तीन कार्य-दिवसों के लिए बढ़ा सकेगा।”

(vi) विनियम 9 में, उप-विनियम (5) का लोप हो जाएगा।

(vii) विनियम 9 में, उप-विनियम (6) में, शब्द तथा चिह्न “राजस्व बॉण्डों (रेविन्यू बॉण्ड्स)”, शब्दों तथा चिह्नों “म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़)” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

(viii) विनियम 10 में, शब्द और चिह्न “संक्षिप्त प्रॉस्पेक्टस (विवरण पत्रिका)” और शब्द “संक्षिप्त प्रॉस्पेक्टस”, जहाँ कहीं भी दिए हुए हों, शब्दों तथा चिह्नों “निबंधन-पत्रक (टर्म शीट)” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

(ix) विनियम 10 में, शब्द “प्रॉस्पेक्टस”, शब्दों तथा चिह्नों “प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट)” से प्रतिस्थापित हो जाएगा।

(x) विनियम 10 में, शब्द “अग्रणी मर्चेन्ट बैंकर”, शब्दों “अग्रणी प्रबंधक” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

(xi) विनियम 10 में, उप-विनियम (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—

"परंतु यह कि जहाँ निर्गमकर्ता (इश्युअर) ऐसा निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) हो जिस पर कंपनी अधिनियम, 2013 लागू होता हो, वहाँ निबंधन-पत्रक (टर्म शीट) को संक्षिप्त प्रॉस्पेक्टस के रूप में पढ़ा जा सकेगा।"

- (xii) विनियम 11 में, शब्द "ऋण प्रतिभूतियों", शब्दों "म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों" से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।
- (xiii) विनियम 11 के पश्चात् और विनियम 12 से पूर्व, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"अति-अभिदान (ओवर सब्सक्रिप्शन)

11क. (1) निर्गमकर्ताओं (इश्युअर्स) को निर्गम के मूल आकार (बेस इश्यू साइज़) के 100% तक की अति-अभिदान (ओवर सब्सक्रिप्शन) की रकम को रखने की अनुमति होगी, किंतु जो उस आकार से जिसकी रेटिंग हुई हो (रेटेड साइज़ से) या प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में यथा उल्लिखित किसी निम्नतर सीमा (यदि कोई हो) से अधिक नहीं होगी।

ल्फ प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल करने वाले निर्गमकर्ताओं (इश्युअर्स) के लिए, अति-अभिदान (ओवर सब्सक्रिप्शन) की रकम, शेल्फ प्रस्ताव दस्तावेज के कुल आकार तक, रखी जा सकेगी।"

- (xiv) विनियम 12 निम्नलिखित प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"आबंटन

12. (1) म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़) के सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) में आबंटन स्टॉक एक्सचेंज की इलेक्ट्रॉनिक बही (बुक) में प्रत्येक आवेदन के अपलोड होने की तारीख के आधार पर किया जाना चाहिए:

परंतु यह कि अति-अभिदान (ओवर सब्सक्रिप्शन) की तारीख को या उसके बाद, आबंटन आवेदकों को अति-अभिदान की सीमा तक आनुपातिक आधार पर किए जा सकेंगे।

(2) निर्गमकर्ता (इश्युअर) और अग्रणी प्रबंधक (लीड मैनेजर) यह सुनिश्चित करेगा (करेंगे) कि ऐसी अवधि के भीतर, जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाए, म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों का आबंटन हो जाता है और / या आवेदन की रकम लौटा दी जाती है या आवेदन की रकम को अनब्लॉक कर दिया जाए।

(3) अग्रणी प्रबंधक (लीड मैनेजर) यह सुनिश्चित करेगा (करेंगे) कि आबंटन (अलॉटमेंट) करना, गैर-कागज़ी प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) को खाते में जमा (क्रेडिट) करना और पैसा लौटाना (रिफंड करना) या आवेदन की रकम को अनब्लॉक करना, जो भी लागू हो, इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाता है।

(4) जहाँ ऊपर उप-विनियम (2) में निर्धारित की गई अवधि के भीतर प्रतिभूतियों का आबंटन नहीं किया जाता है और / या आवेदन की रकम नहीं लौटाई जाती है या आवेदन की रकम को अनब्लॉक नहीं किया जाता है, वहाँ निर्गमकर्ता (इश्युअर) निवेशकों को प्रंद्रह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से और ऐसे समय के भीतर ब्याज अदा करने का वचन देगा जैसा प्रस्ताव दस्तावेज में प्रकट किया गया हो, और अग्रणी प्रबंधक इस बात को सुनिश्चित करेगा (करेंगे)।"

- (xv) विनियम 13 में, शब्द तथा चिह्न "राजस्व बॉण्डों (रेविन्यू बॉण्ड्स)", शब्दों तथा चिह्नों "म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़)" से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

(X) अध्याय-IV में, अध्याय के शीर्षक में, शब्द "ऋण प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता", शब्दों तथा चिह्नों "निजी स्थानन (प्राइवेट प्लेसमेंट) आधार पर निर्गमित म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों" से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

(XI) अध्याय-IV में,-

(i) विनियम 14 निम्नलिखित विनियम से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"निजी स्थानन (प्राइवेट प्लेसमेंट) आधार पर सूचीबद्धता (लिस्टिंग)

14. निर्गमकर्ता (इश्युअर) स्थानन ज्ञापन (प्लेसमेंट मैमोरेण्डम) के माध्यम से निजी स्थानन (प्राइवेट प्लेसमेंट) आधार पर निर्गमित (इश्यू की गई) अपनी म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध (लिस्ट) करा सकेगा।"

(ii) विनियम 15 निम्नलिखित विनियमों से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"प्रारंभिक स्थानन ज्ञापन (प्लेसमेंट मैमोरेण्डम)

14क. (1) जिन म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध (लिस्ट) किए जाने का प्रस्ताव हो, उनका निजी स्थानन (प्राइवेट प्लेसमेंट) लाने से पहले, निर्गमकर्ता (इश्युअर) बोर्ड से रजिस्ट्रीकृत मर्चेट बैंककार (बैंकर) के माध्यम से बोर्ड और स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के पास प्रारंभिक स्थानन ज्ञापन दाखिल करेगा।

(2) निर्गम (इश्यू) का मर्चेट बैंककार (बैंकर) बोर्ड को प्रारंभिक स्थानन ज्ञापन के साथ निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा,-

(क) इन विनियमों की अनुसूची-1 और अनुसूची-1क में यथा उल्लिखित प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र); और

(ख) अनुसूची-11 के फॉर्म-क के अनुसार पूरी तत्परता बरते जाने (ड्यू डिलीजेंस) संबंधी प्रमाणपत्र (सम्यक् तत्परता प्रमाणपत्र)।

(3) बोर्ड, निम्नलिखित तारीखों में से जो अंतिम तारीख हो उस तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर, प्रारंभिक स्थानन ज्ञापन के संबंध में अभिमत, यदि कोई हों, जारी कर सकेगा:

(क) उप-विनियम (1) के तहत प्रारंभिक स्थानन ज्ञापन के प्राप्त होने की तारीख; या

(ख) निर्गमकर्ता (इश्युअर) और / या निर्गम (इश्यू) के मर्चेट बैंककार से संतोषजनक उत्तर के प्राप्त होने की तारीख, जहाँ बोर्ड ने उनसे कोई स्पष्टीकरण या अतिरिक्त जानकारी मांगी हो; या

(ग) किसी विनियामक (रेग्युलेटर) या एजेंसी से स्पष्टीकरण या जानकारी के प्राप्त होने की तारीख, जहाँ बोर्ड ने ऐसे विनियामक या एजेंसी से कोई स्पष्टीकरण या जानकारी मांगी हो; या

(घ) स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी हेतु जारी किए गए पत्र की प्रति के प्राप्त होने की तारीख।

(4) निर्गम (इश्यू) का मर्चेट बैंककार, यथास्थिति, यह सुनिश्चित करेगा कि स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के पास स्थानन ज्ञापन दाखिल करने से पहले प्रारंभिक स्थानन ज्ञापन में सभी टिप्पणियों को उपयुक्त रूप से शामिल कर लिया जाए; और निर्गम (इश्यू) का मर्चेट बैंककार (बैंकर) पूरी तत्परता बरते जाने

(ड्यू डिलीजेंस) संबंधी प्रमाणपत्र (सम्यक् तत्परता प्रमाणपत्र) प्रस्तुत करेगा, जिसका उल्लेख अनुसूची-II के फार्म ख और फॉर्म ग में किया गया है।

(5) डिबेंचर न्यासी, निजी स्थानन (प्राइवेट प्लेस्टमेंट) के खुलने से पहले, बोर्ड को इन विनियमों की अनुसूची-III के अनुसार पूरी तत्परता बरते जाने (ड्यू डिलीजेंस) संबंधी प्रमाणपत्र (सम्यक् तत्परता प्रमाणपत्र) प्रस्तुत करेगा।

न्यूनतम अभिदान

15. प्रति निवेशक (विनिधानकर्ता) अभिदान (सब्सक्रिप्शन) की न्यूनतम रकम दस लाख रुपये होगी।”

(XII) अध्याय-V में,-

(i) विनियम 16 निम्नलिखित विनियम से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“इलेक्ट्रॉनिक निर्गमन (इश्युएंस)

16. म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों के निर्गम (इश्यू) का प्रस्ताव लाने वाला निर्गमकर्ता ऐसा प्रस्ताव ऑन-लाइन प्रणाली के माध्यम से ला सकेगा और वह संबंधित अपेक्षाओं, जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएं, का पालन करेगा।”

(ii) विनियम 17 में, शब्दों “से कम नहीं होगा” के पश्चात्, चिह्न तथा शब्द “, उसी प्रकार से जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए” अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(iii) विनियम 17 के पश्चात् और विनियम 18 से पूर्व, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“पुट या कॉल ऑप्शन

17क. निर्गमकर्ता (इश्युअर) म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों को परिपक्वता (मैच्युरिटी) की तारीख से पहले अपने विकल्प (कॉल) पर वापस मंगा सकेगा या परिपक्वता (मैच्युरिटी) की तारीख से पहले मोचन (रिडेंप्शन) करने का ऐसा अधिकार (पुट) सभी निवेशकों (विनिधानकर्ताओं) को, उनके विकल्प पर, प्रदान कर सकेगा, उसी प्रकार जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए:

परंतु यह कि ऐसे सभी मामलों में, प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) या स्थानन ज्ञापन (प्लेसमेंट मैमोरैण्डम) में विस्तृत प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) किए जाएंगे।”

(iv) विनियम 18 में, -

(क) विनियम के शीर्षक में, और उप-विनियम (1) में, शब्दों “प्रस्ताव दस्तावेज” के पश्चात्, शब्द तथा चिह्न “या स्थानन ज्ञापन (प्लेसमेंट मैमोरैण्डम)” अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उप-विनियम (1) में, शब्दों “प्रस्ताव दस्तावेज” के पश्चात् और शब्द “या स्थानन” से पूर्व, शब्द तथा चिह्न “या निबंधन-पत्रक (टर्म शीट)” अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ग) उप-विनियम (1) में, शब्दों “भ्रामक बना दे” के पश्चात् दिए हुए चिह्न और शब्दों “, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिनके अधीन वे किए जाते हों” का लोप हो जाएगा;

(घ) उप-विनियम (2) में, शब्द “संक्षिप्त प्रॉस्पेक्टस”, शब्दों तथा चिह्नों “निबंधन-पत्रक (टर्म शीट)” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे;

(ड) उप-विनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“(3) प्रस्ताव दस्तावेज या स्थानन ज्ञापन (प्लेसमेंट मैमोरैन्डम) में वे सभी महत्वपूर्ण प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर्स) शामिल किए जाएंगे जो सही और पर्याप्त हों, ताकि आवेदक निवेश के संबंध में सोच-समझकर निर्णय ले सकें।”

(v) विनियम 18 के पश्चात् और विनियम 19 से पूर्व, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्,-

“निर्गम से आए पैसों [निर्गम आगमों (इश्यू प्रोसीड्स)] का उपयोग

18क. (1) म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों के निर्गम (इश्यू) से जुटाए गए पैसों (फंड / निधियों) का उपयोग केवल उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया जाएगा, जिनका उल्लेख प्रस्ताव दस्तावेज या स्थानन ज्ञापन (प्लेसमेंट मैमोरैन्डम) में निर्धारित उद्देश्यों के तहत किया गया हो।

(2) जहाँ निर्गम से आए पैसे किसी एक परियोजना (प्रोजेक्ट) या एक से अधिक परियोजनाओं के लिए रखे गए हों, वहाँ संबद्ध प्राधिकरणों (अथॉरिटीज़) से पहले से जरूरी मंजूरियाँ, यदि लागू हो, ली जाएंगी।

(3) निर्गमकर्ताओं (इश्युअर) का एक बैंक खाता रहेगा जिसमें निर्गम से जुटाई गई रकम निर्गम के बंद होने के ठीक बाद अंतरित (ट्रांसफर) कर दी जाएगी, और ऐसी रकम का उपयोग केवल उल्लिखित परियोजना (परियोजनाओं) के लिए ही किया जाएगा:

परंतु यह और कि निर्गम (इश्यू) का मर्चेन्ट बैंककार, निजी स्थानन (प्राइवेट प्लेसमेंट) के मामले में, सूचीबद्धता (लिस्टिंग) और व्यापारिक (ट्रेडिंग) के संबंध में मिली मंजूरियों की प्रतियों के माध्यम से, निर्गमन बैंककारों (बैंकर्स टू द इश्यू) को यह पुष्टि करेगा कि निर्गम के संबंध में सभी औपचारिकताएँ पूरी कर ली गई हैं और यह कि बैंककार (बैंकर) निर्गमकर्ता को पैसा सौंप सकता है या निर्गम के असफल होने की दशा में पैसा लौटाने (रिफंड करने) हेतु पैसा निर्मुक्त (रिलीज़) कर सकता है।

(4) निर्गमकर्ता (इश्युअर) प्रस्ताव दस्तावेज या स्थानन ज्ञापन में परियोजना के कार्यान्वयन के कार्यक्रम को सारणीबद्ध रूप में प्रकट करेगा और निर्गमकर्ता द्वारा जुटाई गई रकम (निधियों / फंड) का उपयोग उक्त कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा।

निर्गमकर्ता का अंशदान

18ख. म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों के प्रत्येक निर्गमन (इश्युएंस) हेतु निर्गमकर्ता का अंशदान परियोजना (प्रोजेक्ट) की लागतों के बीस प्रतिशत से कम नहीं होगा, और जो उनके आंतरिक संसाधनों या अनुदानों (ग्रांट्स) से किया जाएगा, जो नकद रूप में या वस्तु रूप में हो सकता है।”

(vi) विनियम 19 निम्नलिखित विनियम से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“निलंब खाते (एस्करो अकाउंट) बनाना

19. निर्गमकर्ता (इश्युअर) व्यवस्थित भुगतान प्रणाली बनाएगा और म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों की चुकौती (सर्विसिंग) के उद्देश्य से अलग से निलंब खाते (एस्करो अकाउंट) बनाएगा, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए।”

(vii) विनियम 20 निम्नलिखित विनियम से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड)

20. (1) म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों के निर्गम (इश्यू) को प्रतिभूत करने के लिए न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड) निर्गमकर्ता (इश्युअर) द्वारा डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर ट्रस्टी) के पक्ष में निष्पादित किया जाएगा।

(2) न्यास विलेख में ऐसे खंड शामिल होंगे, जिनका उल्लेख भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993 की अनुसूची-IV में किया गया है:

परंतु यह कि जिस निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) पर कंपनी अधिनियम, 2013 लागू होता है, उसके द्वारा निजी स्थानन (प्राइवेट प्लेसमेंट) के मामले में, न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड) में, अतिरिक्त रूप से, ऐसे खंड शामिल होंगे, जैसा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 71 तथा कंपनी (शेयर पूँजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के अनुमान अपेक्षित है।

(3) न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड) में ऐसा खंड शामिल नहीं होगा, जिससे:

(क) निवेशकों (विनिधानकर्ताओं) के किन्हीं अधिकारों या हितों के संबंध में डिबेंचर न्यासियों (डिबेंचर ट्रस्टीज़) या निर्गमकर्ता (इश्युअर) की बाध्यताएँ और उनके दायित्व सीमित हो जाएँ या समाप्त हो जाएँ;

(ख) अधिनियम, या प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 [सिक्यूरिटीज़ कॉण्ट्रैक्ट्स (रेग्यूलेशन) एक्ट, 1956] या निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (डिपॉजिटरीज़ एक्ट, 1996), तथा बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विनियमों (रेग्यूलेशन्स) और परिपत्रों (सर्कुलर्स) या दिशानिर्देशों (मार्गदर्शक सिद्धांतों / गाइडलाइन्स) के प्रावधान सीमित आदि हो जाएँ या उनसे छूट प्राप्त हो जाए;

(ग) डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर ट्रस्टी) या निर्गमकर्ता अपनी लापरवाही (उपेक्षा) के कारण अथवा स्वयं द्वारा कुछ करने या न करने के कारण हुई हानि या हुए नुकसान के प्रति वे सुरक्षित हो जाएँ।

(4) निर्गम से आएँ पैसे (इश्यू प्रोसीड्स) का उपयोग तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि न्यास विलेख निष्पादित न कर दिया जाए।”

(viii) विनियम 21 निम्नलिखित विनियम से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“मोचन (रिडेंप्शन) और रोल-ओवर

21. (1) निर्गमकर्ता (इश्युअर) प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) या स्थानन ज्ञापन के अनुसार म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों का मोचन (रिडेंप्शन) करेगा।

(2) जहाँ निर्गमकर्ता (इश्युअर) निर्गमित म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों का रोल ओवर करना चाहता हो, वहाँ वह ऐसा केवल उस आशय का विशेष संकल्प (रेज़ोल्यूशन) पारित करके ही करेगा और प्रस्तावित रोल ओवर के संबंध में म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़) के धारकों (होल्डर्स) को इक्कीस दिनों की सूचना (का नोटिस) देगा:

परंतु यह कि, यदि म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों के धारक सूचना (नोटिस) की अवधि के भीतर प्रस्तावित रोल ओवर के लिए सहमति प्रदान नहीं करते, तो निर्गमकर्ता (इश्युअर) ऐसे धारकों की म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों का मोचन (को रिडीम) करेगा।

(3) उप-विनियम (2) में उल्लिखित सूचना (नोटिस) में क्रेडिट रेटिंग के संबंध में और रोल-ओवर के तर्काधार के संबंध में प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) शामिल किए जाएंगे।

(4) निर्गमकर्ता (इश्युअर) म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों के धारकों को सूचना (नोटिस) भेजने से पहले, उन स्टॉक एक्सचेंजों के पास सूचना (नोटिस) और प्रस्तावित संकल्प की एक प्रति दाखिल करेगा, जहाँ ऐसी प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों, ताकि इन्हें उनके वेबसाइटों पर जनता के लिए प्रसारित किया जा सके।

(5) निर्गमित (इश्यू की गई) म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों का रोल-ओवर निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जा सकता है:

(क) म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों के धारकों द्वारा विशेष संकल्प पारित करके रोल-ओवर को मंजूरी प्रदान की गई हो, जिसके लिए ऐसी म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों के मूल्य के अनुसार कम से कम 75% धारकों की सहमति ली गई हो;

(ख) कम से कम एक रेटिंग मोचन (रिडेंप्शन) की नियत तारीख से पूर्व छह महीनों की अवधि के भीतर साख निर्धारण एजेंसी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसी) से प्राप्त की गई हो और उसे उप-विनियम (2) में उल्लिखित सूचना (नोटिस) में प्रकट किया गया हो;

(ग) नया न्यास विलेख (नई ट्रस्ट डीड) ऐसे रोल-ओवर के समय निष्पादित किया जाएगा या मौजूदा न्यास विलेख को कायम रखा जा सकेगा यदि न्यास विलेख में इस प्रकार कायम रखे जाने का प्रावधान हो।

(6) निर्गमकर्ता (इश्युअर) उन सभी धारकों (होल्डर्स) की म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों का मोचन (रिडेंप्शन) करेगा, जिन्होंने रोल-ओवर के प्रति अपनी निश्चित सहमति न दी हो।”

(ix) विनियम 22 निम्नलिखित विनियमों से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य (फेस वैल्यू)

22. म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य (फेस वैल्यू) प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) या स्थानन ज्ञापन (प्लेसमेंट मैमोरैन्डम) में उसी प्रकार प्रकट किया जाएगा, जैसा बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया हो।

दैनिक गणना पद्धति (डे काउंट कन्वेंशन)

22क. म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों पर अदा किए जाने वाले ब्याज की गणना के लिए दैनिक गणना पद्धति ‘एक्चुअल/एक्चुअल’ होगी और जिसकी गणना उसी प्रकार की जाएगी, जैसा बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया हो।

प्रोत्साहनों पर रोक

22ख. निर्गम से जुड़ा कोई भी व्यक्ति निर्गम (इश्यू) में आवेदन करने के संबंध में किसी भी व्यक्ति को किसी प्रोत्साहन की, चाहे नकद रूप में या वस्तु रूप में या सेवाओं के रूप में या किसी अन्य रूप में, किसी भी प्रकार से (चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से) पेशकश नहीं करेगा, किंतु निर्गम के संबंध में प्रदान की गई सेवाओं के लिए फीस या कमीशन अदा किया जा सकेगा।”

(XIII) अध्याय-VI में, अध्याय के शीर्षक में, शब्द “ऋण प्रतिभूतियों” शब्दों “म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

(XIV) अध्याय-VI में,-

(i) विनियम 23 निम्नलिखित विनियम से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“सतत सूचीबद्धता (लिस्टिंग) की शर्तें

23. (1) म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों का सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) लाने वाला या निजी स्थानन (प्राइवेट प्लेसमेंट) आधार पर निर्गमित (इश्यू की गई) म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता (लिस्टिंग) चाहने वाला निर्गमकर्ता (इश्युअर), इन विनियमों की अनुसूची-V में दी हुई सूचीबद्धता की शर्तों का पालन करेगा, जिनमें बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली सतत प्रकटीकरण (डिस्कलोज़र) संबंधी अपेक्षाओं और अन्य अपेक्षाओं का पालन किया जाना भी शामिल है।

(2) जहाँ निर्गमकर्ता (इश्युअर) ऐसा निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) हो जिस पर कंपनी अधिनियम, 2013 लागू होता हो, वहाँ उसके बोर्ड में एक-तिहाई स्वतंत्र निदेशक होंगे, जैसा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 में परिभाषित है।

(3) रेटिंग में होने वाले किसी परिवर्तन को तत्परता से उसी प्रकार प्रसारित किया जाएगा, जैसा वह स्टॉक एक्सचेंज समय-समय पर निर्धारित करे, जहाँ ऐसी प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों।

(4) निर्गमकर्ता (इश्युअर), संबंधित डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर ट्रस्टी), और स्टॉक एक्सचेंज म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों से संबंधित समस्त जानकारी और रिपोर्टें, जिनमें निर्गमकर्ताओं और डिबेंचर न्यासियों द्वारा दाखिल की गई पालन संबंधी रिपोर्टें (कम्प्लायन्स रिपोर्ट) शामिल हैं, अपने-अपने वेबसाइटों पर डालकर निवेशकों (विनिधानकर्ताओं) और आम जनता को प्रसारित करेंगे।

(5) उप-विनियम (3) में उल्लिखित जानकारी डिबेंचर न्यासी, निर्गमकर्ता और स्टॉक एक्सचेंजों के वेबसाइटों पर भी डाली जाएगी।”

(ii) विनियम 24 निम्नलिखित विनियम से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“लेखा और लेखापरीक्षा (ऑडिट)

24. (1) निर्गमकर्ता (इश्युअर) उसी प्रकार लेखे (अकाउंट्स) तैयार करेगा, जैसा विनियम 4 के खंड (ख) में उल्लेख है:

परंतु यह कि यदि निर्गमकर्ता (इश्युअर) ऐसा निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) हो जिस पर कंपनी अधिनियम, 2013 लागू होता हो, तो लेखे (अकाउंट्स) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 एवं 134 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार तैयार किए जाएंगे।

(2) यदि निर्गमकर्ता (इश्युअर) नगरपालिका हो, तो निर्गमकर्ता के लेखों की लेखापरीक्षा (का ऑडिट) नगर निगमों (म्युनिसिपल कारपोरेशन्स) द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्तियों द्वारा की जाएगी, जैसा उसके गठन संबंधी दस्तावेज के तहत अनुमत हो:

परंतु यह कि यदि निर्गमकर्ता (इश्युअर) ऐसा निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) हो जिस पर कंपनी अधिनियम, 2013 लागू होता हो, तो निर्गमकर्ता के लेखों की लेखापरीक्षा लेखापरीक्षक (ऑडिटर) द्वारा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार, की जाएगी।

(iii) विनियम 25 निम्नलिखित विनियम से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) का व्यापार (की ट्रेडिंग) और उनकी रिपोर्टिंग

25. (1) सूचीबद्ध (लिस्टिड) म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों के व्यापारों (ट्रेड) का समाशोधन (की क्लीयरिंग) और निपटान (सेटलमेंट) मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम (क्लीयरिंग

कारपोरेशन) के माध्यम से उसी प्रकार किया जाएगा, जैसा बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया हो।

(2) म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़) के 'ओवर द काउंटर' किए गए व्यापारों (ट्रेड) के मामले में, ऐसे व्यापारों (ट्रेड) की रिपोर्ट राष्ट्रव्यापी व्यापारिक (ट्रेडिंग) टर्मिनल वाले मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को या ऐसे अन्य प्लेटफॉर्म को दी जाएगी, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए।

(3) निर्गमों (इश्यूज़) के संबंध में जानकारी [जैसे निर्गमकर्ता (इश्युअर) के ब्यौरे, लिखत (इंस्ट्रूमेंट) के ब्यौरे, रेटिंगें, रेटिंग में परिवर्तन (रेटिंग माइग्रेशन), कूपन, क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक), आदि] साझे डाटाबेस (कॉमन डाटाबेस) में देनी जरूरी होगी, जैसा बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए।”

(XV) अध्याय-VII में,-

(i) विनियम 26 निम्नलिखित विनियम से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“डिबेंचर न्यासी की बाध्यताएँ

26. (1) म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़) के धारकों (होल्डर्स) के हित का संरक्षण करने के संबंध में जरूरी शक्तियाँ डिबेंचर न्यासी में निहित होंगी:

परंतु यह कि जहाँ निर्गमकर्ता (इश्युअर) ऐसा निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) हो जिस पर कंपनी अधिनियम, 2013 लागू होता हो, वहाँ ऐसी शक्तियों में, ऐसी प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के संस्थागत धारकों (इंस्ट्रुक्शनल होल्डर्स) के परामर्श से, निर्गमकर्ता के बोर्ड में नामिति (नॉमिनी) निदेशक को नियुक्त करने का अधिकार शामिल होगा।

(2) डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर ट्रस्टी) इन विनियमों, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993, न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड) और प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) / स्थानन ज्ञापन (प्लेसमेंट मैमोरैन्डम) के अनुसार, पूरी सतर्कता, तत्परता और निष्ठा से, अपने कर्तव्य निभाएगा और अपने कार्य करेगा।

(3) डिबेंचर न्यासी निर्धारित आमदनी (इयरमाकर्ड रेविन्यू) के संबंध में अलग से बनाए गए निलंब खाते (एस्क्रो अकाउंट) पर नज़र रखेगा (को मॉनीटर करेगा)।

(4) डिबेंचर न्यासी यह सुनिश्चित करेगा कि समस्त महत्वपूर्ण (तात्विक) घटनाओं का सतत आधार पर प्रकटीकरण (डिस्कलोज़र) होता रहे।

(5) डिबेंचर न्यासी इस पर नज़र रखेगा कि इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित बाध्यताएँ पूरी की जाएँ।”

(ii) विनियम 27 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“निर्गमकर्ता और मर्चेन्ट बैंककार की बाध्यताएँ

27. (1) निर्गमकर्ता (इश्युअर) जनता को जारी किए गए या जनता के बीच वितरित किए गए प्रस्ताव दस्तावेजों (ऑफर डॉक्यूमेंट) में समस्त महत्वपूर्ण (तात्विक) तथ्यों को प्रकट करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि प्रस्ताव दस्तावेज में किए गए समस्त प्रकटीकरण सही, उचित तथा पर्याप्त हों, और प्रस्ताव दस्तावेज में कोई भी भ्रामक या असत्य कथन या गलतबयानी न की गई हो।

(2) मर्चेट बैंककार (बैंकर) यह सत्यापित और पुष्टि करेगा (करेंगे) कि प्रस्ताव दस्तावेजों में किए गए प्रकटीकरण सही, उचित तथा पर्याप्त हैं, और यह सुनिश्चित करेगा (करेंगे) कि निर्गमकर्ता इन विनियमों का पालन कर रहा है।

(3) मर्चेट बैंककार यह सुनिश्चित करेगा (करेंगे) कि इन विनियमों की अनुसूची-1 के अनुसार किसी लेनदेन (ट्रांजेक्शन) विशेष से संबंधित समस्त अपेक्षित प्रकटीकरणों (डिस्क्लोज़र्स) संबंधी अपेक्षाओं का पालन किया गया है:

परंतु यह कि जहाँ निर्गमकर्ता (इश्युअर) ऐसा निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) हो जिस पर कंपनी अधिनियम, 2013 लागू होता हो, वहाँ मर्चेट बैंककार यह भी सुनिश्चित करेगा (करेंगे) कि कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के तहत प्रकटीकरणों संबंधी अपेक्षाओं का पालन किया गया है।

(4) निर्गमकर्ता (इश्युअर) म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों के सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) में आवेदन करने वाले आवेदकों के साथ, बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रियाओं के अनुसार, निष्पक्ष तरीके से बर्ताव करेगा।

(5) मर्चेट बैंककार जनता को प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के निर्गम (इश्यू), प्रस्ताव (ऑफर) और वितरण के संबंध में स्वयं द्वारा किए जाने वाले कार्यों (जो भी उन्होंने अपने हाथ में लिए हों) की बाबत पूरी तत्परता बरते जाने (ड्यू डिलीजेंस) के लिए जिम्मेदार रहेंगे।

(6) लागू विनियमों के अनुसार अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों) और निर्गमकर्ता (इश्युअर) या उसकी समूह (ग्रुप) की कंपनियों के बीच कोई भी हित-विरोध नहीं होगा।”

(XVI) अध्याय-VII के पश्चात् और अध्याय-VIII से पूर्व, निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“अध्याय-VIIक

विनियमों के उल्लंघन के मामले में प्रक्रिया

बोर्ड द्वारा निदेश

27क. अधिनियम की धारा 11, 11क, 11ख, 11घ, धारा 12 की उप-धारा (3), अध्याय-VIक और धारा 24 या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 439 के तहत कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड या तो *स्वप्रेरणा से* या सूचना मिलने पर या किसी निरीक्षण अथवा अन्वेषण (इन्वेस्टिगेशन) के पूरा होने पर या उसके दौरान, प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) के हित में, ऐसे निदेश जारी या पारित कर सकेगा, जो भी वह ठीक समझे, जिनमें निम्नलिखित में से कोई एक या सभी शामिल हैं:

- (क) निर्गमकर्ता को सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) में आवेदन करने वाले आवेदकों को आवेदन की रकम लौटाने (रिफंड) करने का निदेश;
- (ख) संबंधित व्यक्तियों को किसी भी प्रकार से प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में आगे और लेनदेन (डील) न करने का निदेश;
- (ग) संबंधित व्यक्तियों को किसी निश्चित अवधि के लिए प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में पहुँच न रखने का निदेश;
- (घ) निर्गमकर्ता या उसके संप्रवर्तकों (प्रोमोटर) या निदेशकों को प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) का और निर्गम (इश्यू) लाने से रोकने का निदेश;
- (ङ) संबंधित व्यक्ति को प्रतिभूतियाँ बेचने आदि का निदेश;

(च) निर्गमकर्ता (इश्युअर) या निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) को प्रतिभूतियों का अंतरण (को ट्रांसफर) न करने का निदेश या प्रतिभूतियों के अंतरण पर आगे रोक लगाए रखने (फ्रीज करने) का निदेश;

(छ) कोई अन्य निदेश, जो भी बोर्ड मामले की परिस्थितियों के मद्देनज़र उपयुक्त और ठीक समझे: परंतु यह कि बोर्ड, या तो ऐसे निदेश जारी करने से पहले या के बाद, उन व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा जिनके खिलाफ निदेश जारी किए गए हों या जारी किए जाने का प्रस्ताव हो: परंतु यह और कि यदि कोई एकपक्षीय निदेश तत्काल जारी करना जरूरी हो, तो बोर्ड प्रभावित व्यक्ति को निर्णय के पश्चात् सुनवाई का अवसर प्रदान कर सकेगा:

परंतु यह भी कि जहाँ निर्गमकर्ता (इश्युअर) नगरपालिका हो, वहाँ बोर्ड उल्लंघन किए जाने या पालन न किए जाने की घटनाओं, आदि (यदि कोई हों) के बारे में केन्द्रीय सरकार और संबंधित राज्य सरकार को सूचित करेगा।”

(XVII) विनियम 28 का लोप हो जाएगा;

(XVIII) अध्याय-VIII में, विनियम 29 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“विनियमों के कड़ाई से लागू होने के संबंध में छूट प्रदान करने की शक्ति

30. बोर्ड, निवेशकों के हित में या प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) के विकास के लिए, इन विनियमों की किसी अपेक्षा के कड़ाई से लागू होने के संबंध में छूट प्रदान कर सकेगा, यदि बोर्ड इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि,-

- (क) वह अपेक्षा प्रक्रिया-संबंधी अपेक्षा या तकनीकी अपेक्षा जैसी है; या
- (ख) इस अपेक्षा से निवेशकों को अनावश्यक कठिनाई हो सकती है; या
- (ग) प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) संबंधी अपेक्षा किसी उद्योग (इंडस्ट्री) विशेष या अमुक वर्ग के निर्गमकर्ताओं के लिए आवश्यक नहीं है; या
- (घ) पालन ऐसे कारणों से नहीं हो पाया जो निर्गमकर्ता के नियंत्रण से परे थे; या
- (ङ) ऐसी छूट प्रतिभूति बाजार के हित में होगी।”

(XIX) अनुसूची-I निम्नलिखित अनुसूची से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“अनुसूची-I

[विनियम 6 एवं 27 देखें]

प्रस्ताव दस्तावेज और स्थानन ज्ञापन में प्रकटीकरण

इस अनुसूची में उल्लिखित समस्त प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज या प्रारंभिक स्थानन ज्ञापन या प्रस्ताव दस्तावेज या स्थानन ज्ञापन, जो भी लागू हो, में किए जाएंगे।

1. अनुदेश:

- (क) समस्त जानकारी संगत जानकारी होगी और अपडेट की हुई होगी। समस्त कथनों आदि का स्रोत और आधार प्रकट किया जाएगा।

- (ख) प्रस्ताव दस्तावेज / स्थानन ज्ञापन (जो भी लागू हो) कंपनी रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करने या उसे मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के पास दाखिल करने से पहले प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज / प्रारंभिक स्थानन ज्ञापन में दिए हुए सभी रिक्त स्थानों में उपयुक्त ब्यौरे आदि भरे जाएंगे।
- (ग) आसान अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि उसमें दी हुई बातें आसानी से समझ आ सकें। निर्गमकर्ता के कारबार के बारे में समझाने के लिए यदि किन्हीं तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो, तो आसान शब्दों में उनका अर्थ स्पष्ट किया जाएगा।
- (घ) जहाँ कहीं भी यह उल्लेख हो कि ब्यौरे दस्तावेज में कहीं और दिए हुए हैं, वहाँ इस संबंध में पर्याप्त संदर्भ (क्रॉस रेफरेंस) दिए जाएंगे और ऐसा करते समय पैराग्राफ के शीर्षक और पृष्ठ संख्या का उल्लेख कर दिया जाएगा।
- (ङ) भविष्य को लेकर ऐसा कोई कथन नहीं किया जाएगा, जिसे साबित न किया जा सके।
- (च) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) एक ही शैली में किए जाएं। यदि उत्तम (प्रथम) पुरुष का इस्तेमाल किया जाए, तो सभी जगह वैसा ही इस्तेमाल किया जाए। ऐसे वाक्यों से बचा जाए, जिनमें उत्तम (प्रथम) पुरुष और अन्य पुरुष दोनों का इस्तेमाल हो।
- (छ) मुद्रा (करंसी) दर्शाते समय एक ही तरह की मानक वित्तीय यूनिट (स्टैंडर्ड फाइनेंशियल यूनिट) का इस्तेमाल किया जाए।

2. लागू होना:

म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों (जिन्हें सूचीबद्ध कराए जाने का इरादा है) का सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) या निजी स्थानन (प्राइवेट प्लेसमेंट) लाने वाला निर्गमकर्ता इस अनुसूची में यथा उल्लिखित प्रकटीकरण करेगा।

3. सामान्य जानकारी:

- (क) निर्गमकर्ताओं का नाम और उनके प्रधान कार्यालय तथा अन्य कार्यालयों का पता
- (ख) निर्गमकर्ता का रजिस्ट्रीकृत (पंजीकृत) और कारपोरेट कार्यालय, यदि लागू हो
- (ग) महापौर (मेयर) / उप महापौर (डिप्टी मेयर) के ब्यौरे (नियुक्ति की तारीख, आदि सहित)
- (घ) आयुक्त / उपायुक्त के ब्यौरे (नियुक्ति की तारीख, आदि सहित)
- (ङ) परियोजना (प्रोजेक्ट) की मंजूरी देने वाली समिति / कराधान(टेक्सेशन)/वित्त (फाइनेंस)/लेखा(अकाउंट्स)/लेखापरीक्षा(ऑडिट)/अवसंरचना(इन्फ्रास्ट्रक्चर) से संबंधित विभिन्न स्थायी समितियों के सदस्यों के ब्यौरे निम्नलिखित फॉर्मेट में:-

नाम और पदनाम	नियुक्ति या त्यागपत्र की तारीख	कब से समिति के सदस्य हैं (यदि त्यागपत्र दे चुके हों)	टिप्पणियाँ

- (च) यदि निर्गमकर्ता एक कंपनी हो, तो निर्गमकर्ता के निदेशक-मंडल के प्रत्येक सदस्य का नाम, पदनाम, पता और डीआईएन
- (छ) निर्गमकर्ता के अनुपालन अधिकारी (कम्प्लायंस ऑफिसर) का नाम, पता, दूरभाष संख्या और ई-मेल आईडी

- (ज) म्युनिसिपल बॉण्डों से संबंधित निवेशक शिकायतें देखने वाले प्रभारी अधिकारी के पूरे ब्यौरे, उसका पता, दूरभाष संख्या, ई-मेल आईडी, आदि
- (झ) निर्गमकर्ता (इश्युअर) का मुख्य लेखा एवं वित्त अधिकारी (चीफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस ऑफिसर) या समकक्ष अधिकारी
- (ञ) लिखत (इंस्ट्रुमेंट्स) के अरेंजर, यदि कोई हों
- (ट) निर्गम (इश्यू) का डिबेंचर न्यासी
- (ठ) निर्गम रजिस्ट्रार (रजिस्ट्रार टू एन इश्यू)
- (ड) निर्गम की साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) एजेंसी (एजेंसियाँ), और
- (ढ) निर्गम के लेखापरीक्षक (ऑडिटर)
- (ण) अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों), निर्गम रजिस्ट्रार (रजिस्ट्रार टू एन इश्यू), निर्गमन बैंककार (बैंकर्स टू एन इश्यू), निर्गम से संबंधित दलाल (ब्रोकर) और सिंडिकेट सदस्य (सदस्यों) के नाम, पते, उनकी दूरभाष संख्याएँ, उनके संपर्क व्यक्ति, उनके वेबसाइट के पते और ई-मेल आईडी; और साथ ही भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के वेबसाइट का यूआरएल जिसके अंतर्गत स्व-प्रमाणित सिंडिकेट बैंकों, निर्गम रजिस्ट्रार (रजिस्ट्रार टू एन इश्यू) और निक्षेपागार सहभागियों (डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स), आदि के विवरण दिए हुए हों, यदि लागू हो।
- (त) कंपनी सचिव (कंपनी सेक्रेटरी), कानूनी सलाहकार, हामीदारों (अंडरराइटर्स) और निर्गमन बैंककारों के नाम, पते, उनकी दूरभाष संख्याएँ और ई-मेल आईडी।
- (थ) डिबेंचर न्यासी (न्यासियों) के (नाम) नामों का उल्लेख इस आशय के कथन के साथ किया जाएगा कि डिबेंचर न्यासी (न्यासियों) ने अपनी नियुक्ति हेतु, निर्गमकर्ता को अपनी सहमति दे दी है। ऋण प्रतिभूतियों (डेट सिक्यूरिटीज़) के धारकों (होल्डर्स) को बाद में भेजी जाने वाली सभी सूचनाओं में भी इसका उल्लेख किया जाना आवश्यक है।
- (द) निवेशक शिकायत निवारण व्यवस्था

4. निर्गमकर्ता और निर्गमकर्ता की पूँजी संरचना (कैपिटल स्ट्रक्चर) के बारे में:

- (क) गठन संबंधी दस्तावेज
- (ख) निर्गमकर्ता की पूँजी संरचना के ब्यौरे, यदि लागू हो।
- (ग) निर्गमकर्ता के प्रबंधन ढाँचे (मैनेजमेंट स्ट्रक्चर) का ब्यौरा।
- (घ) निर्गमकर्ता के शेयरधारिता स्वरूप (शेयरहोल्डिंग पैटर्न) के साथ-साथ निर्गमकर्ता के शीर्ष 10 शेयरधारक, यदि लागू हो।
- (ङ) संकल्प, जिसके अंतर्गत उधार लेना प्राधिकृत किया गया हो और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं की सूची।
- (च) म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों के आबंटन के लिए जरूरी संकल्प (संकल्पों) के ब्यौरे।
- (छ) यदि निर्गमकर्ता कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित कोई निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) हो, तो संगम ज्ञापन (मैमोरैंडम ऑफ असोसिएशन) और संगम अनुच्छेद (आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन), यदि लागू हो
- (ज) पिछले 1 वर्ष में निर्गमकर्ता के प्रबंधन के पुनर्गठन या उसकी पुनर्संरचना के ब्यौरे

- (झ) हाथ में ली गई सभी परियोजनाओं या सभी प्रस्तावित परियोजनाओं के व्यौरे [लागत के व्यौरे देते हुए और साथ ही यह बताते हुए कि फाइनेंसिंग (वित्तपोषण) कहाँ से की गई]
- (ञ) उन परियोजनाओं से संबंधित पूँजी संरचना, जिनके लिए पैसा जुटाए जाने का प्रस्ताव है।
- (ट) प्रस्तावित परियोजना के लिए पूँजी अनुदान (कैपिटल ग्रांट) और इस संबंध में प्राप्त रकम
- (ठ) वार्षिक आधार पर राज्य वित्त आयोग (स्टेट फाइनेंस कमीशन) से प्राप्त अनुदान (ग्रांट) के व्यौरे

5. निर्गम (इश्यू) के उद्देश्य:

- (क) प्रस्तावित निर्गम से आए पैसे किसी एक परियोजना या एक से अधिक परियोजनाओं के लिए स्पष्ट रूप से निर्धारित (इयरमार्क) किए जाएँगे [परियोजना के स्थान, संयंत्र (प्लांट) एवं मशीनरी, तकनीक, प्रक्रिया आदि के व्यौरे भी दिए जाएँगे];
- (ख) जहाँ निर्गमकर्ता एक से अधिक क्रियाकलाप (एक्टिविटी) या परियोजना (प्रोजेक्ट) हाथ में लेना चाहता हो (जैसे डाइवरसिफिकेशन, आधुनिकीकरण, या विस्तार आदि), वहाँ परियोजना की कुल लागत, यथास्थिति, क्रियाकलाप के अनुसार या परियोजना के अनुसार
- (ग) जहाँ निर्गमकर्ता (इश्युअर) परियोजना का कार्यान्वयन चरणबद्ध रूप से करता हो, वहाँ प्रत्येक चरण (जिसके अंतर्गत वह चरण भी शामिल है जिसका कार्यान्वयन पहले ही किया जा चुका हो, यदि कोई हो) में लगने वाली लागत का व्यौरा अलग से दिया जाएगा।
- (घ) परियोजना के घटकों के लिए निवेश योजना और साथ ही उसके चरणों का उल्लेख किया जाए तथा उसकी फाइनेंसिंग का भी व्यौरा दिया जाए, जिसकी मंजूरी, यथास्थिति, स्थानीय प्राधिकरण या एजेंसी द्वारा दी गई हो।
- (ङ) परियोजना के कार्यान्वयन का कार्यक्रम
- (च) परियोजना को शुरू करने और उसे पूरा करने संबंधी बेंचमार्क, जिनमें परियोजना के सभी घटकों के लिए नियत तारीखें शामिल हैं
- (छ) विनियामक (रेग्युलेटरी) मंजूरी (यदि अपेक्षित हो) के व्यौरे और उसकी स्थिति
- (ज) निर्गम संबंधी खर्च:

निर्गम संबंधी खर्च (खर्च की प्रत्येक मद के अंतर्गत किए गए खर्च के व्यौरों सहित), जिनमें शामिल है – निम्नलिखित को / के संबंध में अदा की जाने वाली फीस के व्यौरे अलग-अलग दिए जाएँ [रकम के अनुसार, निर्गम (इश्यू) के कुल खर्चों के प्रतिशत के रूप में और निर्गम के कुल आकार (कुल इश्यू साइज़) के प्रतिशत के रूप में]:

- (क) अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों) की फीस [हामीदारी (अंडरराइटिंग) संबंधी कमीशन सहित]
- (ख) दलाली (ब्रोकेज), बिक्री संबंधी कमीशन और अपलोड किए जाने संबंधी फीस
- (ग) निर्गम रजिस्ट्रार (रजिस्ट्रार टू एन इश्यू)
- (घ) कानूनी सलाहकार
- (ङ) विज्ञापन और विपणन (मार्केटिंग) संबंधी खर्च

- (च) विनियामक (स्टॉक एक्सचेंजों सहित)
- (छ) निर्गम (इश्यू) से संबंधित स्टेशनरी का मुद्रण (प्रिंटिंग) और उसका वितरण
- (ज) अन्य, यदि कोई हो तो उल्लेख करें।

6. कर लाभ:

निर्गमकर्ता (इश्युअर) और उसके निवेशकों हेतु कोई विशेष कर लाभ (प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर से संबंधित कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत)

7. निर्गम (इश्यू) से संबंधित जानकारी:

- (क) निर्गम (इश्यू) / लिखत (इंस्ट्रूमेंट) संबंधी विनियम - संबंधित ब्यौरे [संबंधित अधिनियम (एक्ट), भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश (गाइडलाइन्स), आदि]।
- (ख) रेटिंग एजेंसियों द्वारा अपनाए गए रेटिंग के तर्काधार (तर्काधारों) को [जो निर्गम (इश्यू) के खुलने की तारीख तक की स्थिति के अनुसार एक वर्ष से अधिक पुराने न हों] / रेटिंग एजेंसियों द्वारा क्रेडिट रेटिंग हेतु जारी किए गए पत्र को [जो निर्गम (इश्यू) के खुलने की तारीख तक की स्थिति के अनुसार एक महीने से अधिक पुराना न हो] प्रकट किया जाएगा। उन सभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के नाम, जिनसे क्रेडिट रेटिंग (जिसमें वह रेटिंग भी शामिल है, जिसे स्वीकार न किया गया हो) प्राप्त की गई हो।
- (ग) क्रेडिट वृद्धि (क्रेडिट एन्हांसमेंट) की व्यवस्थाएँ, यदि कोई हों (पूरे ब्यौरों, यदि कोई हों, सहित)।
- (घ) उन सभी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के नाम, जहाँ ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़) को सूचीबद्ध (लिस्ट) कराए जाने का प्रस्ताव हो [नामनिर्दिष्ट (डेज़िग्नैटेड) स्टॉक एक्सचेंज का नाम बताते हुए]।
- (ङ) नियत तारीखों को ब्याज के भुगतान और/या मूलधन के मोचन (रिडेंप्शन) में चूक होने की दशा में, कूपन की दर के अलावा, अदा किया जाने वाला अतिरिक्त ब्याज।
- (च) ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़) की सूचीबद्धता (लिस्टिंग) में देरी होने के मामले में, निर्गमकर्ता (इश्युअर) द्वारा उस तारीख से दंडस्वरूप अदा किया जाने वाला ब्याज जिस तारीख को आबंटन (अलॉटमेंट) हुआ माना गया हो।
- (छ) डिबेंचर मोचन आरक्षिति (डिबेंचर रिडेंप्शन रिज़र्व) / ऐसी अन्य आरक्षिति (रिज़र्व) का सृजन - संबंधित विनियम, जो लागू हों।
- (ज) आवेदन की प्रक्रिया
- (झ) भुगतान की तारीखों को तय करने और उनमें बदलाव आदि करने की प्रक्रिया [उन दिनों के संबंध में, जब किसी कारणवश (जैसे बैंक में अचानक अवकाश हो जाने की वजह से) भुगतान न किया जा सकता हो]।
- (ञ) 'भुगतान की शर्तें आदि' और आबंटन करने तथा प्रमाणपत्र जारी किए जाने / डीमैट खाते में जमा करवाने की प्रक्रिया तथा समय-सूची।

- (ट) आवेदन कैसे करें, आवेदन फॉर्मों तथा प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) की उपलब्धता और भुगतान का माध्यम ।
- (ठ) पिछले 5 वर्षों में निर्गमित (इश्यू) की गई म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़) की शर्तों आदि में परिवर्तन [अर्थात् कूपन, परिपक्वता (मैच्यूरिटी), कॉल / पुट ऑप्शन आदि में परिवर्तन]
- (ड) म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़) के आबंटन और उनके निर्गम (इश्यू) की प्रक्रिया और समय-सूची ।
- (ढ) ब्याज / मूलधन की चुकौती हेतु 'एस्क्रो पेमेंट व्यवस्था' के ब्यौरे दिए जाएं ।

8. वित्तीय जानकारी:

I. पिछले 3 वर्षों के वित्तीय विवरणों के अनुसार निम्नलिखित ब्यौरे (सारणी में) :

- (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के संक्षिप्त तुलन-पत्र, आय-व्यय लेखा तथा प्राप्ति और भुगतान खाता (प्रमुख शीर्षों सहित) ।
- (ख) उस वेबपेज का लिंक दिया जाए, जहाँ से म्युनिसिपल बॉडी के संपूर्ण वित्त-संबंधी विवरण (फाइनेंशियल्स) देखे जा सकें ।
- (ग) पिछले तीन वर्षों के बजट संबंधी दस्तावेजों की प्रति, जिनमें यह बताया गया हो कि वास्तव में वित्तीय स्थिति कैसी रही और/या जिसमें संशोधित अनुमान दिए गए हों [संबद्ध पक्षकार संव्यवहारों (रिलेटेड पार्टी ट्रांज़ैक्शन) के ब्यौरों सहित] ।
- (घ) वित्तीय मापदंड:

वित्त-संबंधी मुख्य आँकड़े	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष
आमदनी (रेविन्यू) आय			
आमदनी (रेविन्यू) व्यय (ब्याज को छोड़कर)			
'ऑपरेटिंग रेविन्यू' अधिशेष			
ब्याज संबंधी खर्च			
मूलधन की चुकौती (किंतु सिंकिंग फंड से नहीं)			
सिंकिंग फंड में अंशदान			
आमदनी (रेविन्यू)			

अधिशेष			
पूँजीगत आय (कैपिटल इनकम)			
पूँजीगत व्यय			
पूँजी अधिशेष			
समग्र अधिशेष			
जमाएँ (डिपॉजिट) और अग्रिम (एडवांस) [शुद्ध]			
प्रारंभिक नकदी / बैंक शेष			
नकदी / बैंक शेष में परिवर्तन			
अंतिम नकदी / बैंक शेष			
सिंकिंग फंड से ऋण चुकाती			
सिंकिंग फंड का प्रारंभिक शेष			
सिंकिंग फंड में परिवर्तन			
सिंकिंग फंड का अंतिम शेष			
कुल ऋण (डैट)			
कुल व्यय / कुल आमदनी (रेविन्यू) का अनुपात			
नकदी अधिशेष / कुल आमदनी (रेविन्यू)			
कर्ज चुकाती (डैट सर्विस) / कुल आमदनी (रेविन्यू) का अनुपात			

II. पिछले तीन वर्षों के दौरान आमदनी (रेविन्यू) के शीर्ष पाँच स्रोतों के ब्यौरे

प्राप्त आमदनी का प्रकार	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक
	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष
कखग 1			
कखग 2			
कखग 3			
कखग 4			
कखग 5			

III. कितना संपत्ति कर एकत्र हुआ, उसके व्यौरे

विवरण	की गई मांग		कितना वसूल हुआ			समग्र वसूली अनुपात		वर्तमान वसूली अनुपात
	बकाया	वर्तमान	कुल	वर्तमान	बकाया	कुल		
वित्तीय वर्ष								
वित्तीय वर्ष								
वित्तीय वर्ष								

IV. ई-गवर्नेंस, जल आपूर्ति के संबंध में लागत वसूली, कचरा प्रबंधन (सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट / एसडब्ल्यूएम), संपत्ति कर, दोहरी प्रविष्टि लेखांकन (डबल एंट्री अकाउंटिंग), और अन्यो के संबंध में सुधारों (जो केन्द्रीय सरकार और संबंधित प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित किए जाएँ) की स्थिति

V. उधार

(क) सबसे अंत की तिमाही की समाप्ति तक की स्थिति के अनुसार निर्गमकर्ता (इश्युअर) के उधारों के व्यौरे:-

(ख) जमानती ऋण (सिक्योर्ड लोन) संबंधी सुविधाओं के व्यौरे:-

उधार देने वाले का नाम	सुविधा का प्रकार	मंजूर रकम	बकाया मूलधन की रकम	चुकोती की तारीख / कब-कब की जाएगी	जमानत (सिक्यूरिटी)

(ग) गैर-जमानती ऋण (अनसिक्योर्ड लोन) संबंधी सुविधाओं के व्यौरे:-

उधार देने वाले का नाम	सुविधा का प्रकार	मंजूर रकम	बकाया मूलधन की रकम	चुकोती की तारीख / कब-कब की जाएगी

(घ) एनसीडी / बॉण्डों के ब्यौरे:-

डिबेंचर/ बॉण्ड सीरीज़	एनसीडी/ बॉण्ड की अवधि/ परिपक्वता की अवधि	कूपन	रकम	आवंटन की तारीख	मोचन (रिडेंप्शन) की तारीख/ कब-कब क्रिया जाएगा	क्रेडिट रेटिंग	जमानती/ गैर- जमानती	जमानत (सिक्यूरिटी)

(ङ) शीर्ष दस डिबेंचर धारकों (होल्डर्स) की सूची (..... तक की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.		डिबेंचर धारकों का नाम	रकम

टिप्पणी : शीर्ष दस धारकों के ब्यौरे दिए जाएँ [मूल्य के अनुसार, सभी बकाया डिबेंचर निर्गमों (डिबेंचर इश्यू) हेतु संचयी आधार पर] ।

(च) वाणिज्यिक पत्र (कमर्शियल पेपर) के ब्यौरे:- सबसे अंत की समाप्त तिमाही तक की स्थिति के अनुसार बकाया वाणिज्यिक पत्रों (कमर्शियल पेपर्स) का कुल अंकित मूल्य (फेस वेल्यू) बताई जाए और इसका विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया जाए :-

परिपक्वता (मैच्यूरिटी) की तारीख	बकाया रकम

(छ) शेष लिए गए उधारों के ब्यौरे

(ज) लिए हुए किन्हीं बकाया उधारों के ब्यौरे तथा नकद राशि की जगह कुछ और लेकर जारी (निर्गमित / इश्यू) की गई ऋण प्रतिभूतियों (चाहे पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, प्रीमियम पर या डिस्काउंट पर, या विकल्प के अनुसरण में) के ब्यौरे,

VI. पर्याप्त आमदनी (रेविन्यू) और आमदनी के पर्याप्त स्रोत [समय पर चुकौती (सर्विसिंग) तथा मोचन (रिडेंप्शन) हेतु]

VII. आस्ति-देयता असंतुलन (असेट लाइबिलिटी मिसमैच) हो जाने की स्थिति में उसे कम करने के लिए उठाए जाने वाले कदम

9. कानूनी कार्यवाहियों आदि से संबंधित जानकारी और अन्य जानकारी:

(क) लंबित मुकदमे और महत्वपूर्ण घटनाएं :

लंबित मुकदमे [निर्गमकर्ता (इश्युअर) / उसके निदेशकों / संप्रवर्तकों (प्रोमोटर्स) / समनुषंगियों (सब्सीडियरीज़) से संबंधित] :

- (i) सभी दांडिक कार्यवाहियाँ (क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स);
- (ii) विनियामक प्राधिकरणों (रेग्युलेटरी अथॉरिटीज़) और सांविधिक प्राधिकरणों (स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़) द्वारा की गई सभी कार्रवाइयाँ;
- (iii) पिछले पाँच वित्तीय वर्षों के दौरान संप्रवर्तकों (प्रोमोटर्स) के खिलाफ भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) या स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा की गई अनुशासनिक कार्रवाई [जिसमें शास्ति (पेनल्टी) लगाने के संबंध में की गई कार्रवाई भी शामिल है] और लंबित कार्रवाई;
- (iv) प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के संबंध में किए गए दावे (समेकित रूप से) - मामलों की संख्या और कुल रकम के ब्यौरे देते हुए;
- (v) अन्य लंबित मुकदमे - महत्ता (मैटिरियलिटी) की उस नीति के अनुसार, जो निर्गमकर्ता (इश्युअर) के निदेशक-मंडल द्वारा निर्धारित की गई हो और प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) / स्थानन जापन (प्लेसमेंट मैमोरैण्डम) में प्रकट की गई हो।

(ख) लेनदारों के प्रति बकाया राशि:

- (i) निर्गमकर्ता के निदेशक-मंडल द्वारा निर्धारित की गई महत्ता (मैटिरियलिटी) संबंधी नीति के आधार पर, लेनदारों के ब्यौरे जिनमें लेनदारों की समेकित संख्या और कुल रकम के ब्यौरे भी दिए जाएं;
- (ii) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइसेस) के प्रति बकाया राशियों के संबंध में समेकित जानकारी - मामलों की संख्या और कुल रकम के ब्यौरे अलग से देते हुए;
- (iii) बड़े लेनदारों के प्रति बकाया राशियों के बारे में पूरे ब्यौरे (ऐसे प्रत्येक बड़े लेनदार का नाम और उनके प्रति बकाया राशि का उल्लेख करते हुए) कंपनी के वेबसाइट पर डाले जाएंगे और साथ ही उनका वेब-लिंक भी बताया जाएगा।

(ग) यदि प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) / प्रारंभिक स्थानन जापन (प्लेसमेंट मैमोरैण्डम) दाखिल करने के बाद उपरोक्तानुसार कोई मुकदमा चले, कोई महत्वपूर्ण घटना घट जाए या लेनदारों के प्रति कुछ बकाया हो जाए, आदि-आदि, तो इन तथ्यों का उल्लेख प्रस्ताव दस्तावेज / स्थानन जापन में उपयुक्त रूप में किया जाएगा। यदि ऐसा कोई मामला न हो, तो प्रस्ताव दस्तावेज / स्थानन जापन में इस संबंध में स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है।

(घ) अंतिम तुलन-पत्र की तारीख के बाद से घटी महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रस्ताव दस्तावेज या स्थानन जापन में अलग से दर्शाया जाएगा।

(ङ) ऐसा विवरण दिया जाए, जिसमें प्रत्येक महत्वपूर्ण संविदा (काण्ट्रैक्ट) एवं करार (एग्रीमेंट) के बारे में यह बताया जाए कि वे किस तारीख को हुई या हुए और उनमें पक्षकार (उनमें पार्टियाँ) कौन-कौन हैं :

परंतु यह कि मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज ऐसे और ब्यौरे या दस्तावेज मंगा सकेगा, जो भी वह ठीक समझे।

(च) निर्गम (इश्यू) के समय घटी कोई महत्वपूर्ण घटना आदि या हुआ कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन, जिसका वित्त-संबंधी स्थिति (फाइनेंशियल्स) / क्रेडिट क्वालिटी पर असर पड़ता हो [उदाहरणार्थ निर्गमकर्ता

(इश्युअर) के खिलाफ कोई महत्वपूर्ण विनियामक (रेग्युलेटरी) कार्यवाहियाँ, जिनकी वजह से बड़ी देनदारियाँ बन गई हों, पुनर्संरचना (रीस्ट्रक्चरिंग) आदि हुई हो], और जिससे निर्गम (इश्यू) पर या म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों (म्युनिसिपल डैट सिक्यूरिटीज़) में निवेश करने / निवेश करते रहने के संबंध में निवेशक के निर्णय पर असर पड़ सकता हो।

- (छ) ऐसी कोई रकम आदि अदा न किए जाने के ब्यौरे (यदि कोई हों), जो कानूनी तौर पर अदा की जानी जरूरी हो।
- (ज) पिछले 3 वर्षों में, किसी भी प्रकार के मीयादी ऋणों (टर्म लोन), निर्गमकर्ता (इश्युअर) द्वारा निर्गमित (जारी / इश्यू की गई) ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़) और अन्य वित्तीय लिखत (फाइनेंशियल इन्स्ट्रूमेंट) के संबंध में ब्याज और मूलधन की अदायगी में हुई चूक (चूकों) और / या हुई देरी के ब्यौरे।

10. सरकारी मंजूरियाँ:

- (क) भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, आदि (जो भी लागू हो) की ओर से निवेश संबंधी मंजूरियाँ, आशय-पत्र (लेटर ऑफ इंटेन्ट) या उद्योग संबंधी लाइसेंस (इंडस्ट्रियल लाइसेंस), और वित्तीय सुदृढ़ता या कथनों की सटीकता के संबंध में जिम्मेदारी न लिए जाने के बारे में केंद्रीय सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी विनियामक प्राधिकरण (रेग्युलेटरी अथॉरिटी) की घोषणा।
- (ख) सभी सरकारी और अन्य मंजूरियाँ, जो निर्गमकर्ता (इश्युअर) और महत्वपूर्ण समनुषंगियों (सब्सिडियरीज़) के कारोबार तथा कामकाज आदि को चलाने के लिए जरूरी हों।

11. निर्गमकर्ता (इश्युअर) द्वारा वचन:

निर्गमकर्ता द्वारा निम्नलिखित वचन दिए जाएँगे:

- (क) कि वह प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) या स्थानन ज्ञापन (प्लेसमेंट मैमोरेण्डम) में उल्लिखित दस्तावेज डिबेन्चर न्यासी (ट्रस्टी) को इलेक्ट्रॉनिक रूप (सॉफ्ट कॉपी) में प्रस्तुत करेगा;
- (ख) कि निर्गम (इश्यू) के संबंध में प्राप्त शिकायतों का निपटारा शीघ्रता से और संतोषप्रद रूप से करेगा;
- (ग) कि जिन स्टॉक एक्सचेंजों में प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) सूचीबद्ध (लिस्ट) की जानी हों, उन स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता और व्यापार (ट्रेडिंग) शुरू किए जाने के संबंध में जरूरी औपचारिकताओं को पूरा करने हेतु, बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई अवधि के भीतर, सभी कदम उठाए जाएँगे;
- (घ) संबंधित म्युनिसिपल बॉन्ड के महापौर (मेयर) और आयुक्त (कमिश्नर) द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा, जिसमें यह उल्लेख हो कि प्रस्ताव दस्तावेज / स्थानन ज्ञापन में सही, उचित और पर्याप्त जानकारी दी गई है, ताकि निवेशक प्रस्तावित निर्गम (इश्यू) में अपने निवेश के संबंध में सोच-समझकर निर्णय ले पाने में समर्थ हो सकें।
- (ङ) यदि निर्गमकर्ता (इश्युअर) ऐसा निगमित निकाय (बॉन्ड कारपोरेट) हो जिस पर कंपनी अधिनियम, 2013 लागू होता हो, तो निर्गमकर्ता के निदेशक (निदेशकों) द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा, जिसमें यह उल्लेख हो कि प्रस्ताव दस्तावेज / स्थानन ज्ञापन में सही, उचित और पर्याप्त जानकारी दी गई है, ताकि निवेशक प्रस्तावित निर्गम (इश्यू) में अपने निवेश के संबंध में सोच-समझकर निर्णय ले पाने में समर्थ हो सकें।
- (च) निर्गमकर्ता के बोर्ड या उसकी स्थायी समिति द्वारा ऐसा कथन किया जाएगा कि निर्गम (इश्यू) से आया पूरा पैसा एक अलग बैंक खाते में अंतरित (ट्रांसफर) कर दिया जाएगा।
- (छ) सार्वजनिक प्रस्ताव (पब्लिक ऑफर) के माध्यम से लाए गए पिछले निर्गम (इश्यू) में जुटाए गए पैसे में से कितने पैसे का इस्तेमाल कर लिया गया और कितने पैसे का इस्तेमाल नहीं किया गया, इसके ब्यौरे प्रकट किए जाएँगे और तब तक तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) में प्रकट किए जाते रहेंगे जब तक कि ऐसे पिछले निर्गम

से आए पैसे में से कुछ भी पैसा इस्तेमाल हेतु शेष बचा हो, और साथ ही यह भी उल्लेख किया जाएगा कि इन पैसों का इस्तेमाल किन उद्देश्यों से किया गया और उन प्रतिभूतियों (सिक्क्यूरिटीज़) या अन्य प्रकार की वित्तीय आस्तियों (फाइनेंशियल असेट्स) के ब्यौरे भी दिए जाएंगे जिनमें वह पैसा लगाया गया (निवेश किया गया) हो जिसका इस्तेमाल नहीं हुआ था।

12. प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज

- (क) उस संकल्प (रेज़ोल्यूशन) की प्रति, जिसके अंतर्गत उधार लेने के संबंध में प्राधिकृत किया गया हो, और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं की सूची।
- (ख) न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड) की प्रति।
- (ग) वे दस्तावेज, जो निर्गम (इश्यू) के संबंध में निष्पादित किए जा चुके हों या जिनका निर्गम के संबंध में निष्पादन किए जाएंगे।

13. जोखिम कारक:

- (क) जोखिम कारक (रिस्क फैक्टर) ऐसे फॉण्ट में [कम से कम दस पॉइंट के आकार (साइज़) में] छपवाए जाएंगे, जिससे साफ-साफ पढ़ा जा सके।
- (ख) जोखिम कारकों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाएगा - वे कारक जो परियोजना (प्रोजेक्ट) से संबंधित हों तथा निर्गमकर्ता (इश्युअर) की आंतरिक कार्यप्रणाली से संबंधित हों, और वे कारक जो बाहरी हों तथा निर्गमकर्ता के नियंत्रण से परे हों।
- (ग) जोखिम कारकों का निर्धारण उनकी महत्ता के आधार पर किया जाएगा। ऐसा करते समय, निम्नलिखित पर विचार किया जाएगा:
 - i. हो सकता है कि कुछ जोखिम उतने महत्वपूर्ण न लगें, लेकिन दूसरे जोखिमों के साथ आंके जाने पर वही जोखिम काफी महत्वपूर्ण नज़र आए।
 - ii. हो सकता है कि कुछ जोखिमों के असर को आंका न जा सके, लेकिन उनका असर गहरा पड़े।
 - iii. हो सकता है कि कुछ जोखिम आज उतने महत्वपूर्ण न लगें, लेकिन आगे चलकर उनका खासा असर पड़ सकता हो।
- (घ) प्रत्येक जोखिम कारक को निम्नानुसार दर्शाया जाएगा :
 - i. निर्गमकर्ता द्वारा आंका गया जोखिम।
 - ii. जोखिम को दूर करने के लिए प्रस्ताव, यदि कोई हों।
- (ङ) जोखिम कारकों (रिस्क फैक्टर्स), जिनमें परियोजना संबंधी जोखिम (प्रोजेक्ट रिस्क), प्रचालन संबंधी जोखिम (ऑपरेशनल रिस्क), क्रेडिट रिस्क, अर्थसुलभता (लिक्विडिटी) के जोखिम आदि शामिल हैं, के संबंध में विस्तृत प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र)।
- (च) परियोजना से संबंधित जोखिम कारकों के संबंध में प्रबंध-मंडल (मैनेजमेंट) की राय आदि।

14. ऐसे अन्य ब्यौरे, जो प्रस्तावित निर्गम (इश्यू) में निवेश करने के संबंध में सोच-समझकर निर्णय लेने हेतु निवेशकों के लिए जरूरी हों।”

अनुसूची-1 के पश्चात् और अनुसूची-11 से पूर्व, निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्,-

“अनुसूची-1क

[विनियम 6 एवं 14क देखें]

निबंधन-पत्रक (टर्म शीट)

प्रस्ताव (ऑफर) का सार

इस खंड में निम्नलिखित जानकारी (जो भी लागू हो) का सार दिया जाएगा:

- (क) निर्गमकर्ता का मुख्य कारोबार (अधिक से अधिक 100 शब्दों में);
- (ख) निर्गम का आकार (इश्यू साइज़);
- (ग) निर्गम के उद्देश्य (सारणी में);
- (घ) लेखापरीक्षा संबंधी अभिमत (ऑडिट क्वालिफिकेशन) [यदि कोई हों] - वित्तीय विवरणों सहित;
- (ङ) लंबित मुकदमों की संक्षिप्त सारणी और "लंबित मुकदमे और महत्वपूर्ण घटनाएँ" शीर्षक संबंधी खंड का प्रति-संदर्भ (क्रॉस-रेफरेंस)।
- (च) "जोखिम कारक" शीर्षक संबंधी खंड का प्रति-संदर्भ (क्रॉस-रेफरेंस)
- (छ) आकस्मिक (कंटिजेंट) देनदारियों (देयताओं) की संक्षिप्त सारणी और निर्गमकर्ता की आकस्मिक देनदारियों (देयताओं) का प्रति-संदर्भ (क्रॉस-रेफरेंस), जैसा रीस्टेटिड वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया हो।
- (ज) पिछले तीन वर्षों के संबद्ध पक्षकार संव्यवहार (रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन) का सारांश और संबद्ध पक्षकार संव्यवहारों का प्रति-संदर्भ (क्रॉस-रेफरेंस), जैसा वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया हो।
- (झ) ब्याज / मूलधन की चुकौती हेतु 'एस्क्रो पेमेंट व्यवस्था' के ब्यौरे।

संक्षिप्त निबंधन-पत्रक (टर्म शीट) उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों (म्युनिसिपल डैट सिक्यूरिटीज़) (या उनकी सीरीज़) के निर्गम (इश्यू) से संबंधित जानकारी और ऐसी कोई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होगी, जो ठीक समझी जाए:-

प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) का नाम	
निर्गमकर्ता (इश्युअर)	
लिखत (इंस्ट्रूमेंट) का प्रकार	
वरीयता-क्रम	
निर्गम (इश्यू) का माध्यम	
पात्र निवेशक	
सूचीबद्धता (लिस्टिंग) [उस स्टॉक एक्सचेंज (उन स्टॉक एक्सचेंजों) के नाम सहित, जहाँ उसे सूचीबद्ध (लिस्ट) कराया जाएगा तथा सूचीबद्धता की समय-सीमा सहित]	
लिखत (इंस्ट्रूमेंट) की रेटिंग	
निर्गम का आकार (इश्यू साइज़)	
अति-अभिदान (ओवरसब्सक्रिप्शन) की रकम को रखने का विकल्प	
निर्गम (इश्यू) के उद्देश्य	
निर्गम से आए पैसों (इश्यू प्रोसीड्स) के इस्तेमाल के ब्यौरे	
कूपन दर	
कर-योग्य / कर-मुक्त	
कूपन दर का बढ़ना / घटना	

कूपन भुगतान की आवृत्ति	
कूपन भुगतान की तारीखें	
कूपन का प्रकार	
कूपन रीसेट प्रोसेस (जिसमें दरें, स्प्रेड, प्रभावी तारीख, अधिकतम एवं निम्नतम ब्याज दर, आदि शामिल हैं)	
दैनिक गणना पद्धति (डे काउण्ट बेसिस)	
आवेदन की रकम (एप्लीकेशन मनी) पर ब्याज	
परिपक्वता काल	
मोचन (रिडेंप्शन) की तारीख	
मोचन की रकम	
मोचन प्रीमियम / डिस्काउंट	
निर्गम (इश्यू) की कीमत	
छूट (डिस्काउंट), जिस पर प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) निर्गमित (इश्यू) की जाती हो और ऐसी छूट के परिणामस्वरूप मिलने वाला प्रतिफल (यील्ड)	
पुट ऑप्शन की तारीख	
पुट ऑप्शन की कीमत	
कॉल ऑप्शन की तारीख	
कॉल ऑप्शन की कीमत	
पुट सूचित करने का समय	
कॉल सूचित करने का समय	
अंकित मूल्य (फेस वैल्यू)	
म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों के लिए न्यूनतम आवेदन [या उसके गुणज (मल्टिपल) में]	
निर्गम (इश्यू) का समय <ol style="list-style-type: none"> 1. निर्गम खुलने की तारीख 2. निर्गम बंद होने की तारीख 3. पे-इन की तारीख 4. वह तारीख जिस तारीख को आबंटन हुआ माना जाए 	
लिखत (इंस्ट्रूमेंट) किस रूप में जारी (निर्गमित / इश्यू) की जाएगी	

लिखत में ट्रेडिंग किस रूप में की जाएगी	
लिखत का निपटान (सेटलमेंट) किस रूप में किया जाएगा	
निक्षेपागार (डिपॉज़िटरी)	
बिजनेस डे कन्वेंशन	
रिकॉर्ड तिथि	
लेनदेन (संव्यवहार / ट्रांजैक्शन) संबंधी दस्तावेज	
संवितरण (वितरण / डिस्बर्समेंट) से पहले की शर्तें	
संवितरण के बाद की शर्तें	
चूक की घटनाएँ	
क्रॉस डिफॉल्ट क्लॉज़ से संबंधित प्रावधान	
डिबेंचर न्यासी की भूमिका और उसकी जिम्मेदारियाँ	
किस कानून के तहत विनियमित है, और क्षेत्राधिकार	

XXI. अनुसूची-II निम्नलिखित अनुसूची से प्रतिस्थापित हो जाएगी, अर्थात्,-

“अनुसूची-II

[विनियम 7 एवं 14 देखें]

फॉर्म-क

अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों) / मर्चेट बैंककार (बैंकर) द्वारा प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्रॉफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) / प्रारंभिक स्थानन ज्ञापन (प्लेसमेंट मेमोरैंडम) के साथ दिए जाने वाले 'पूरी तत्परता बरते जाने' (ड्यू डिलिजेंस) संबंधी प्रमाणपत्र का फॉर्मेट

प्रति,

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

महोदय,

विषय: _____ (निर्गमकर्ता / इश्युअर) द्वारा _____ का निर्गम (इश्यू)

हम यह पुष्टि करते हैं कि:

- (1) हमने उपरोक्त निर्गम (इश्यू) से संबंधित दस्तावेजों और अन्य संबंधित दस्तावेजों की जाँच-पड़ताल कर ली है।

- (2) ऐसी जाँच-पड़ताल और निर्गमकर्ता, उसके निदेशकों तथा अन्य अधिकारियों, अन्य एजेंसियों के साथ हुई चर्चाओं और निर्गम (इश्यू) के उद्देश्यों से संबंधित कथनों, निर्गमकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं अन्य कागजात की विषय-वस्तु के स्वतंत्र सत्यापन के आधार पर:
- (क) बोर्ड के पास दाखिल किया गया प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज / प्रारंभिक स्थानन ज्ञापन उन दस्तावेजों, सामग्री और कागजात के अनुरूप है, जो निर्गम (इश्यू) के लिए महत्वपूर्ण हैं;
- (ख) निर्गम (इश्यू) से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण कानूनी अपेक्षाओं का विधिवत् रूप से पालन कर लिया गया है, जो इस निमित्त बोर्ड, केंद्रीय सरकार और किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की गई हैं; और
- (ग) प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज / प्रारंभिक स्थानन ज्ञापन में किए गए महत्वपूर्ण प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) सही और पर्याप्त हैं, ताकि निवेशक प्रस्तावित निर्गम (इश्यू) में निवेश करने के संबंध में सोच-समझकर निर्णय ले सकें, और ऐसे प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) कंपनी अधिनियम, 2013, इन विनियमों की अपेक्षाओं और अन्य लागू कानूनी अपेक्षाओं के अनुसार किए गए हैं।
- (3) प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज / प्रारंभिक स्थानन ज्ञापन में जिन मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) का उल्लेख है, वे सभी मध्यवर्ती बोर्ड से रजिस्ट्रीकृत हैं और यह कि आज की तारीख में ऐसा रजिस्ट्रीकरण मान्य है और यह कि इन मध्यवर्तियों में से किसी भी मध्यवर्ती को किसी भी विनियामक प्राधिकरण (रेग्युलेटरी अथॉरिटी) द्वारा कामकाज करने से विवर्जित नहीं किया गया है।
- (4) यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी इंतजाम किए जाएंगे कि निर्गम (इश्यू) के अनुसरण में प्राप्त होने वाला पैसा एक अलग बैंक खाते में जमा या अंतरित (ट्रांसफर) हो जाए।
- (5) हम भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों (म्युनिसिपल डैट सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता] विनियम, 2015 के अनुसार विज्ञापनों से संबंधित प्रावधानों का पालन करेंगे।
- (6) _____ (तारीख) को कंपनी रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर किए गए और नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल किए गए प्रस्ताव दस्तावेज या स्थानन ज्ञापन को उपयुक्त रूप से अपडेट कर दिया गया था, जिसकी सूचना बोर्ड को दे दी गई थी, और यह कि उक्त तारीख तक की स्थिति के अनुसार उक्त प्रस्ताव दस्तावेज या स्थानन ज्ञापन में निर्गमकर्ता के बारे में सभी महत्वपूर्ण प्रकटीकरण किए गए हैं।
- (7) निर्गमकर्ता (इश्युअर) की प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) को गैर-कागजी रूप देने (डीमैट करने) के संबंध में निक्षेपागारों (डिपॉजिटरीज़) के साथ करार (एग्रीमेंट) कर लिए गए हैं।

हम एक नोट संलग्न कर रहे हैं, जिसमें 'पूरी तत्परता बरते जाने' (ड्यू डिलिजेंस) की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, जो, लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार, प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज / प्रारंभिक स्थानन ज्ञापन में उल्लिखित अवधि के संबंध में हमने अपनाई है।

हम एक जाँच-सूची (चेकलिस्ट) संलग्न कर रहे हैं, जिसमें इन विनियमों के लागू प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक विनियम के पालन की पुष्टि की गई है, और जिसमें विनियम की संख्या, विनियम के प्रावधान, पालन की स्थिति, प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज / प्रारंभिक स्थानन ज्ञापन की पृष्ठ संख्या (जहाँ संबंधित विनियम का पालन किया गया हो) और हमारी टिप्पणियों, यदि कोई हों, का उल्लेख किया गया है।

स्थान: (हस्ताक्षर एवं आधिकारिक मुहर)

तारीख: अग्रणी प्रबंधक / मर्चेट बैंककार

फार्म-ख

निर्गम (इश्यू) के खुलने से पहले अग्रणी प्रबंधक (लीड मैनेजर) / मर्चेट बैंककार द्वारा प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) या स्थानन ज्ञापन (प्लेसमेंट मैमोरेण्डम) दाखिल करते समय 'पूरी तत्परता बरते जाने' (ड्यू डिलिजेंस) संबंधी प्रमाणपत्र का फॉर्मेट

प्रति,

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

महोदय / महोदया,

विषय: _____ द्वारा _____ का निर्गम (इश्यू)

- हम यह पुष्टि करते हैं कि न तो निर्गमकर्ता (इश्युअर) को और न ही उसके संप्रवर्तकों (प्रोमोटर्स) या निदेशकों या अन्य अधिकारियों को, बोर्ड द्वारा पारित किए गए किसी आदेश या निदेश के माध्यम से, पूँजी बाजार (कैपिटल मार्केट) में पहुँच रखने से प्रतिषिद्ध किया गया है। हम यह भी पुष्टि करते हैं कि प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) या स्थानन ज्ञापन (प्लेसमेंट मैमोरेण्डम) में जिन मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरी) का उल्लेख है उनमें से किसी भी मध्यवर्ती को किसी विनियामक प्राधिकरण (रेग्युलेटरी अथॉरिटी) द्वारा कामकाज करने से विवर्जित नहीं किया गया है।
- हम यह पुष्टि करते हैं कि निर्गमकर्ता (इश्युअर) से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) प्रस्ताव दस्तावेज में कर दिए गए हैं और यह प्रमाणित करते हैं कि इस निर्गम (इश्यू) के माध्यम से प्रस्तावित म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता (लिस्टिंग) और उनकी ट्रेडिंग (उनके व्यापार) के शुरू होने तक निर्गम के संबंध में घटी किसी महत्वपूर्ण घटना की सूचना उन सभी समाचारपत्रों में सार्वजनिक सूचनाओं / विज्ञापनों के माध्यम से दी जाएगी, जिनमें निर्गम से पूर्व विज्ञापन और निर्गम के खुलने या बंद होने से संबंधित विज्ञापन दिए गए हों।
- हम यह पुष्टि करते हैं कि प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) या स्थानन ज्ञापन (प्लेसमेंट मैमोरेण्डम) में वे सभी प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) कर दिए गए हैं, जिनका उल्लेख भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों (म्युनिसिपल डैट सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता] विनियम, 2015 में किया गया है।
- हम यह पुष्टि करते हैं कि कंपनी अधिनियम, 2013, यदि लागू हो, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 [सिक्यूरिटीज़ कॉण्ट्रेक्ट्स (रेग्यूलेशन) एक्ट, 1956], भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी एक्ट, 1992) तथा उनके तहत जारी किए गए नियमों, विनियमों (रेग्यूलेशन्स), दिशानिर्देशों (गाइडलाइन्स), परिपत्रों (सर्कुलर्स) में दिए हुए सभी संबंधित प्रावधानों आदि का पालन कर लिया गया है।
- हम यह पुष्टि करते हैं कि _____ [नामनिर्दिष्ट (डेज़िग्रेटेड) स्टॉक एक्सचेंज] के पास दाखिल किए गए प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) / प्रारंभिक स्थानन ज्ञापन (प्लेसमेंट मैमोरेण्डम) के संबंध में प्राप्त सभी टिप्पणियों / शिकायतों का उपयुक्त रूप से निवारण कर लिया गया है।

स्थान: (हस्ताक्षर एवं आधिकारिक मुहर)

तारीख: अग्रणी प्रबंधक / मर्चेट बैंककार

फॉर्म-ग

प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) / स्थानन ज्ञापन (प्लेसमेंट मैमोरेन्डम) दाखिल किए जाने के बाद घटी महत्वपूर्ण घटनाओं के प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) की दशा में अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों) / मर्चेन्ट बैंककार (बैंककारों) द्वारा दिए जाने वाले 'पूरी तत्परता बरते जाने' (ड्यू डिलीजेंस) संबंधी प्रमाणपत्र का फॉर्मेट

प्रति,

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

महोदय,

विषय: _____ (निर्गमकर्ता / इश्युअर) द्वारा _____ का निर्गम (इश्यू)

हम यह पुष्टि करते हैं कि निर्गम (इश्यू) के संबंध में सभी महत्वपूर्ण प्रकटीकरण (आज की तारीख तक के) _____ (तारीख) को कंपनी रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर किए गए और नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल किए गए प्रस्ताव दस्तावेज या स्थानन ज्ञापन के माध्यम से कर दिए गए हैं।

स्थान: (हस्ताक्षर एवं आधिकारिक मुहर)

तारीख: अग्रणी प्रबंधक / मर्चेन्ट बैंककार

XXII. अनुसूची-III निम्नलिखित अनुसूची से प्रतिस्थापित हो जाएगी, अर्थात्,-

“अनुसूची-III

[विनियम 7 एवं 14 देखें]

निर्गम के खुलने से पहले डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर ट्रस्टी) द्वारा दिए जाने वाले 'पूरी तत्परता बरते जाने' (ड्यू डिलीजेंस) संबंधी प्रमाणपत्र का फॉर्मेट

प्रति,

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

महोदय / महोदया,

विषय: _____ (निर्गमकर्ता / इश्युअर) द्वारा _____ का निर्गम (इश्यू)

हम, ऊपर उल्लिखित आगामी निर्गम के डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर ट्रस्टी), निम्नानुसार कथन करते हैं कि:

(1) हमने उपरोक्त निर्गम (इश्यू) से संबंधित दस्तावेजों और अन्य संबंधित दस्तावेजों की जाँच-पड़ताल कर ली है।

- (2) ऐसी जाँच-पड़ताल के आधार पर और निर्गमकर्ता (इश्युअर), उसके महापौर (मेयर) / उप महापौर (डिप्टी मेयर) / निदेशकों तथा अन्य अधिकारियों, अन्य एजेंसियों के साथ हुई चर्चाओं के आधार पर और विभिन्न संबंधित दस्तावेजों के संबंध में स्वतंत्र रूप से किए गए सत्यापन के आधार पर,-
- (क) हम यह पुष्टि करते हैं कि निर्गमकर्ता (इश्युअर) ने ऋण देयताओं की चुकौती के लिए 'एस्करो पेमेंट व्यवस्था' के संबंध में समुचित प्रावधान कर लिया है, और
- (ख) हमने ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़) की चुकौती (की सर्विस) के संबंध में निर्गमकर्ता (इश्युअर) की क्षमता के प्रति अपनी संतुष्टि कर ली है।

स्थान:

(हस्ताक्षर एवं आधिकारिक मुहर)

तारीख:

निर्गम का डिबेंचर न्यासी"

- XXIII. अनुसूची-IV में, चिह्न तथा शब्द, "_____ नगर निगम या _____ लिमिटेड (या कारपोरेट म्युनिसिपल एंटीटी)", चिह्नों तथा शब्दों "_____ नगर निगम या _____ [निर्गमकर्ता (इश्युअर) का नाम]" से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।
- XXIV. अनुसूची-V, निम्नलिखित अनुसूची से प्रतिस्थापित हो जाएगी, अर्थात्, -

"अनुसूची-V"

[विनियम 23 का उप-विनियम (1) देखें]

निर्गमकर्ताओं (इश्युअर्स) द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र)

- i. महत्वपूर्ण प्रतिकूल परिवर्तन, जिनसे बॉण्डों की चुकौती (सर्विसिंग) करने की क्षमता पर असर पड़ता हो।
- ii. पूर्व भुगतान (प्री-पेमेंट) के लिए प्रस्ताव, परिपक्वता (मैच्यूरिटी) से पहले बिक्री / खरीद के मामले में बॉण्ड का मूल्यांकन, आदि।
- iii. महत्वपूर्ण अनुपात, जैसे ऋण इक्विटी अनुपात (डैट इक्विटी रेशियो), ऋण चुकौती कवरेज अनुपात (डैट सर्विस कवरेज रेशियो), ब्याज चुकौती कवरेज अनुपात (इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो), आदि।
- iv. बॉण्डों की चुकौती (सर्विसिंग), क्रेडिट वृद्धि (क्रेडिट एन्हांसमेंट) सुविधाओं और निवेशकों की शिकायतों एवं उनके निवारण के संबंध में छमाही विवरणी (रिटर्न)।"

अजय त्यागी, अध्यक्ष,

[विज्ञापन -III/4/असा./229/19]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (नगरपालिकाओं द्वारा ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/006, 15 जुलाई 2015 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (नगरपालिकाओं द्वारा ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2015 तत्पश्चात्,-

- (1) 15 फरवरी, 2017 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (नगरपालिकाओं द्वारा ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/032 द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 27th September, 2019

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

**(ISSUE AND LISTING OF DEBT SECURITIES BY MUNICIPALITIES)
(AMENDMENT) REGULATIONS, 2019**

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/40.—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities by Municipalities) Regulations, 2015, namely,—

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities by Municipalities) (Amendment) Regulations, 2019.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities by Municipalities) Regulations, 2015,—

- (I) the title, the words “Issue and Listing of Debt Securities by Municipalities” shall be substituted by the words “Issue and Listing of Municipal Debt Securities”.
- (II) In the opening para, for the words “debt securities by municipalities”, the words, “municipal debt securities” shall be substituted;
- (III) In regulation 1, in sub-regulation (1), the words “Issue and Listing of Debt Securities by Municipalities” shall be substituted by the words “Issue and Listing of Municipal Debt Securities”.
- (IV) In regulation 2, in sub-regulation (1), clause (d) to (q) shall be substituted by the following clauses, namely,—

“(d) “constitution document” shall mean the Central or State Act, Rules, Regulations or charter under which the issuer has been established or incorporated or notified;

(e) “credit enhancement” shall mean any arrangement including subordination, insurance, letter of credit, over-collateralization, undertakings, guarantees, letter of comfort etc.;

(f) “designated stock exchange” shall mean a recognized stock exchange in which securities of an issuer are listed or proposed to be listed and which is chosen by the issuer as a designated stock exchange for the purpose of a particular issue of municipal debt securities under these regulations;

(g) “draft offer document” shall mean the draft offer document filed with the Board in relation to a public issue under these regulations;

(h) “fugitive economic offender” shall mean an individual who is declared a fugitive economic offender under section 12 of the Fugitive Economic Offenders Act, 2018 (17 of 2018);

(i) “general purposes” include such identified purposes for which no specific amount is allocated or any amount so specified towards general purpose or any such purpose by whatever name called, in the draft offer document or the offer document;

(j) “interest payment account” shall mean the account wherein the interest amount due to be paid by the borrower/issuer is deposited.

(k) “institutional investor” shall have the same meaning as assigned to it under Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital And Disclosure Requirements) Regulations, 2018;

(l) “issuer” shall mean any municipality or any Statutory Body or Board or corporation, Authority, Trust or Agency established or notified by any Central or State Act or any Special Purpose Vehicle notified by the State Government or Central Government subject to the condition that it undertakes one or more functions that may be entrusted under Article 243W of the Constitution of India:

Provided that any structure set up under the Pooled Finance Development Fund Scheme of the Government of India or a body corporate to whom the Companies Act, 2013 applies, which offers or proposes to offer municipal debt securities in accordance with these regulations shall also be deemed to be an issuer subject to condition that it is set up by the State Government(s) or Central Government for the purpose of raising funds for a person performing one or more functions entrusted under Article 243W of the Constitution of India.

(m) "municipal debt securities" shall mean non-convertible debt securities which create or acknowledge indebtedness, and include debenture, bonds and such other securities of an issuer;

(n) "municipality" shall mean an institution of self-government constituted under Article 243Q of the Constitution of India;

(o) "national municipal accounts manual" shall mean the municipal accounting manual formulated by the Central Government from time to time;

(p) "no lien escrow account" shall mean the account created for the specific purpose of receiving and disbursing funds towards discharge of contractual obligations;

(q) "offer document" shall mean any document including an electronic document described or issued as an offer document or prospectus or shelf offer document and include any document or advertisement, whereby the subscription to municipal debt securities are invited by the issuer from public;

(r) "placement memorandum" shall mean any document including an electronic document which is serially numbered and copies of which are circulated only to select investors and is related to an issue made on private placement basis;

(s) "private placement" shall mean any offer of municipal debt securities or invitation to subscribe to municipal debt securities to a select group of persons by an issuer through issue of a placement memorandum to not more than two hundred persons in a financial year, which shall not intend to result in, directly or indirectly, the municipal debt securities becoming available for subscription or purchase by persons other than those receiving the offer or invitation:

Provided that,-

iii. for a body corporate to which the Companies Act, 2013 applies, it shall mean an offer or invitation made in terms of section 42 of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, through issue of a placement memorandum;

iv. any offer or invitation made to qualified institutional buyers shall not be considered while calculating the limit of two hundred persons;

(t) "preliminary placement memorandum" shall mean the placement memorandum filed with the Board and the stock exchange(s) in relation to a private placement under these regulations;

(u) "public issue" shall mean an offer or invitation by an issuer to public to subscribe to the municipal debt securities, which is not in the nature of a private placement;

(v) "qualified institutional buyer" shall have the same meaning as assigned to it under Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital And Disclosure Requirements) Regulations, 2018;

(w) "schedule" shall mean a schedule annexed to these regulations;

(x) "shelf offer document" shall mean an offer document in respect of which the municipal debt securities included therein are offered for subscription to the public in one or more offers over a period not exceeding one year from the date of opening of the first offer of securities under that offer document, without the issue of a further offer document:

Provided that for a body corporate to whom the Companies Act, 2013 applies, it shall have the same meaning as assigned to "shelf prospectus" in section 31 of Companies Act, 2013;

(y) "sinking fund account" shall mean the account that is created specifically for repayment of municipal debt securities;

(z) "specified" includes specified by regulations or by a general or special order or circular issued by the Board;

(za) "wilful defaulter" shall mean a person or an issuer who or which is categorized as a wilful defaulter by any bank or financial institution (as defined under the Companies Act, 2013) or a

consortium thereof, in accordance with the guidelines on wilful defaulters issued by the Reserve Bank of India.”

- (V) In regulation 2, in sub-regulation (2), the words, symbol and numbers “or the Companies Act, 2013”, shall be omitted.

- (VI) In regulation (3), clauses (a) and (b) shall be substituted by the following clauses, namely,-

“(a) issuance and listing of municipal debt securities by an issuer by way of public issuance; and

(b) issuance and listing of municipal debt securities by an issuer on private placement basis which are intended/disclosed to be listed on a recognised stock exchange.”

- (VII) In Chapter II, in the Chapter heading, after the word “**ELIGIBILITY**”, the words and symbol, “**AND CONDITIONS**”, shall be inserted.

- (VIII) In Chapter II, -

- (iv) before regulation 4, the following regulation shall be inserted, namely, -

“Reference date

3A. Unless otherwise provided in these Regulations, an issuer making an offer of municipal debt securities shall satisfy the conditions of these Regulations as on the date of filing of the draft offer document or preliminary placement memorandum with the Board and also as on the date of filing the offer document or placement memorandum with the Board or upon registering the offer document or placement memorandum with the Registrar of Companies, as the case may be.”

- (v) regulation 4 shall be substituted by the following regulation, namely,-

“Eligible issuers.

4. No issuer shall be eligible to issue municipal debt securities under these regulations, unless the following criteria are complied with:

- (a) the issuer, proposing to issue municipal debt securities is eligible to raise funds under its constitution document;
- (b) the accounts of issuer shall be prepared in accordance with any of the following:
 - v. National Municipal Accounts Manual or;
 - vi. Municipal Accounts Manual as adopted by the respective State Governments; or
 - vii. Accounting standards, applicable to issuers, as prescribed under the Companies Act or;
 - viii. Accounting standards/policies, applicable to issuers, as specified in their constitution document.
- (c) the issuer has not defaulted in repayment of debt securities or loans obtained from banks or financial institutions, during the preceding three hundred and sixty five days;
- (d) no order or direction of restraint, prohibition or debarment by the Board is in force against the issuer or its promoters or its directors from accessing the securities market;
- (e) an issuer or its promoter, group company or director(s) thereof, should not have been named in the list of the wilful defaulters;
- (f) any of its promoter or director(s) has not been declared as a fugitive economic offender(s);

Provided that where the issuer is a body corporate to which the Companies Act, 2013 applies or is a Special Purpose Vehicle, which is set up for the purpose of raising funds for an person for performing one or more functions entrusted under Article 243W of the Constitution of India, the requirements at clauses (b) and (c) above shall be complied by the person being financed;

- (vi) After regulation 4 the following regulations shall be inserted, namely,-

“In-principle approval

4A. The issuer shall make an application to one or more recognized stock exchange for listing of such securities therein:

Provided that where the application is made to more than one recognised stock exchanges, the issuer shall choose one of them as the designated stock exchange:

Explanation.-For any subsequent issue, the issuer may choose a different stock exchange as a designated stock exchange subject to the requirements of this regulation.

Credit Rating

4B. The issuer shall obtain credit rating from at least one credit rating agency registered with the Board, which shall be disclosed in the offer document or placement memorandum, as applicable:

Provided that where credit ratings are obtained from more than one credit rating agency, all the ratings, including the unaccepted ratings, shall be disclosed in the offer document or placement memorandum, as applicable.

Dematerialisation

4C. The issuer shall enter into an arrangement with a depository registered with the Board for dematerialisation of the municipal debt securities that are proposed to be issued, in accordance with the Depositories Act, 1996, rules and regulations made thereunder.

Debenture trustee

4D. The issuer shall appoint a debenture trustee registered with the Board in accordance with the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 1993.

Mandatory Listing

4E. (1) The issuer shall make an application for listing to one or more recognised stock exchanges in the manner specified by the Board.

(2) In case the issuer fails to obtain listing or trading permission from any of the recognized stock exchanges where the municipal debt securities were proposed to be listed, it shall refund the entire monies received within seven days of receipt of intimation from stock exchange or in case of multiple stock exchange(s) within seven days from the earliest intimation rejecting the application for listing of municipal debt securities, and if any such money is not repaid after the issuer becomes liable to repay it, the issuer shall be liable to repay that money with interest at the rate of fifteen percent per annum till such refund is made:

Provided that where the issuer is a body corporate to which the Companies Act, 2013, applies every director of the company who is an officer in default shall also be jointly and severally liable to repay that money with interest.”

(IX) In Chapter III, -

(i) regulation 5, shall be substituted by the following regulation, namely, -

“Eligibility Conditions for public issue

5. No issuer shall make a public issue of municipal debt securities unless the following conditions are complied with:

- (a) the issuer has surplus income as per its Income and Expenditure Statement in any of the immediately preceding three financial years or as per any other financial criteria as may be specified by the Board from time to time:

Provided that where the issuer is a body corporate to which the Companies Act, 2013 applies, it shall not have negative net worth in any of immediately preceding three financial years;

Provided that where the issuer is a body corporate to which the Companies Act, 2013 applies or is a Special Purpose Vehicle, which is set up for the purpose of raising funds for an person for performing one or more functions entrusted under

Article 243W of the Constitution of India, the requirements at clause (a) shall be complied by the person being financed;

(b) Any other conditions as may be specified by the Board from time to time.”

(ii) regulation 6, shall be substituted by the following regulation, namely, -

“Disclosures in the draft offer document and offer document.

6. (1) The draft offer document and offer document shall contain true, fair and material disclosures, which are necessary for the subscribers of the municipal debt securities to take an informed investment decision.

(2) Without prejudice to the generality of sub-regulation (1), the issuer and the lead manager shall ensure that the draft offer document contains the following:

- (a) disclosures specified in Schedule I and Schedule IA of these regulations;
- (b) additional disclosures as may be specified by the Board:

Provided that in case the issuer is a body corporate to which the Companies Act, 2013 applies, the issuer and the lead manager shall ensure that the draft offer document and the offer document also contain the disclosures as mandated by the Companies Act, 2013 and the Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014.

(3) The lead manager(s) shall exercise due diligence and satisfy themselves about all aspects of the issue including the veracity and adequacy of disclosures in the draft offer document and the offer document.”

(iii) after regulation 6 and before regulation 7, the following regulation shall be inserted, namely, -

“Appointment of Merchant Banker and other intermediaries

6A. (1) The issuer shall appoint one or more merchant bankers, which are registered with the Board, as lead manager(s) to the issue.

(2) Where the issue is managed by more than one lead manager, the rights, obligations and responsibilities, relating to disclosures, allotment, refund and underwriting obligations among other things, if any, of each lead manager shall be predetermined and be disclosed in the draft offer document and the offer document.

(3) The issuer shall, in consultation with the lead manager(s), appoint other registered intermediaries after the lead manager(s) have independently assessed their capability to carry out their obligations.

(4) Where there is only one lead manager he shall not be an associate (as defined under the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992) of the issuer.

(5) In case there are multiple lead managers, at least one lead manager to the issue shall not be an associate (as defined under the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992) of the issuer

(6) If the lead manager is an associate of the issuer, it shall disclose itself as an associate of the issuer and its role shall be limited to marketing of the issue.”

(iv) regulation 7, shall be substituted by the following regulation, namely, -

“Filing of draft offer document

7. (1) No issuer shall make a public issue of municipal debt securities unless a draft offer document has been filed with the Board and designated stock exchange through the lead manager:

Provided that where an issuer has filed a shelf offer document, not more than four public issuances shall be made through a single shelf offer document.

- (2) The lead manager shall submit the following to the Board along with the draft offer document, -
- (a) certificate confirming that a written agreement has been entered into between the issuer and the lead manager;
 - (b) a due diligence certificate as per Form A of Schedule II.
- (3) The Board may specify changes or issue observations, if any, on the draft offer document within twenty one days from the later of the following dates:
- a) the date of receipt of the draft offer document under sub-regulation (1); or
 - b) the date of receipt of satisfactory reply from the lead manager(s), where the Board has sought any clarification or additional information from them; or
 - c) the date of receipt of clarification or information from any regulator or agency, where the Board has sought any clarification or information from such regulator or agency; or
 - d) the date of receipt of a copy of in-principle approval letter issued by the stock exchange(s).
- (4) The draft offer document filed with the designated stock exchange shall be made public by posting the same on the website of the designated stock exchange for seeking public comments for a period of fifteen days from the date of filing the draft offer document with such exchange and shall be available for download in PDF / HTML formats.
- (5) The draft offer document shall also be displayed on the website of the issuer, lead manager(s) and the stock exchanges where the municipal debt securities are proposed to be listed.
- (6) The lead manager shall ensure that the draft offer document specifies the names and contact details of the compliance officer of the lead manager, the officer concerned and the project officer, wherever applicable, of the issuer including their postal and email address, telephone and fax numbers.
- (7) The lead manager shall after expiry of the period stipulated in sub-regulation (4) file with the Board the details of the comments received by them or the issuer from the public in respect of the draft offer document, during the period stipulated in sub-regulation (4), alongwith the consequential changes, if any, that are required to be made in the draft offer document.
- (8) If the Board specifies any changes or issues observations, the issuer and lead manager(s) shall carry out such changes in the draft offer document and shall submit to the Board the updated draft offer document complying with the observations issued by the Board and highlighting all changes made in the draft offer document and before filing the offer document with the stock exchange or Registrar of Companies, as the case may be.
- (9) The lead manager(s) shall submit the following documents to the Board after issuance of observations by the Board or after expiry of the period stipulated in sub-regulation (3) of this regulation if the Board has not issued observations:
- a) a statement certifying that all changes, suggestions and observations made by the Board have been incorporated in the offer document or the placement memorandum;
 - b) a due diligence certificate as per Form B and Form C of Schedule II.
- (10) A copy of draft and final offer document along-with a soft copy shall also be forwarded to the Board, simultaneously with filing of these documents with the designated stock exchange.
- (11) The issuer filing a shelf offer document shall also file a copy of an information memorandum, containing all material facts including changes in the financial position as have occurred between the previous offer or first offer or subsequent offer of municipal

debt securities, with the recognised stock exchanges and the Board and in case the issuer is a body corporate to whom the Companies Act, 2013 applies such issuer shall also file the same with the Registrar of Companies.

(12) The lead manager shall, furnish to the Board a due diligence certificate as per Schedule II of these regulations with the offer document prior to opening of the public issue:

Provided that where the issuer is a body corporate to which the Companies Act, 2013 applies, the lead manager shall, prior to filing of the final offer document with the Registrar of Companies, furnish to the Board a due diligence certificate as per Schedule II of these regulations.

(13) The debenture trustee, shall, prior to the opening of the public issue, furnish to the Board a due diligence certificate as per Schedule III of these regulations.

(14) The issuer and the lead manager(s) shall ensure that the offer documents are hosted on the websites as required under these regulations and its contents are the same as the versions as filed with the Registrar of Companies, Board and the stock exchanges, as applicable.

(15) The lead manager(s) and the stock exchanges shall provide copies of the offer document to the public as and when requested and may charge a reasonable sum for providing a copy of the same.”

- (v) regulation 8, shall be substituted by the following regulation, namely, -

“Period of subscription

8. (1) Except as otherwise provided in these regulations, public issue of municipal debt securities shall be kept open for at least three working days.

(2) The issuer may extend the bidding period disclosed in the offer document, in case of force majeure, banking strike or similar circumstances, for a minimum period of three working days.”

- (vi) in regulation 9, sub-regulation (5) shall be omitted.
- (vii) in regulation 9, in sub-regulation (6), the words “revenue bonds” shall be substituted by the words, “municipal debt securities”.
- (viii) in regulation 10, including the heading to the regulation, the words, “abridged prospectus” wherever found, shall be substituted by the words “term sheet”.
- (ix) in regulation 10, the word, “prospectus” shall be substituted by the words “offer document”.
- (x) in regulation 10, the word, “lead merchant banker” shall be substituted by the words “lead manager”.
- (xi) in regulation 10, in sub-regulation (1), the following proviso will be inserted, namely,-

“Provided that where the issuer is a body corporate to which the Companies Act, 2013 applies, the term sheet may be read as abridged prospectus.”

- (xii) in regulation 11, after the words “issue of” and before the words “debt securities”, the word “municipal” shall be inserted.
- (xiii) after regulation 11 and before regulation 12, the following regulation shall be inserted, namely,-

“Over subscription

11A. (1) Issuers shall be allowed to retain the over-subscription money up to 100% of the Base Issue size but not exceeding the rated size or any lower limit as specified in the offer document, if any.

(2) For the issuers filing a shelf offer document, oversubscription may be retained up to the total size of the shelf offer document.”

(xiv) regulation 12 shall be substituted by the following regulation, namely,-

“Allotment

12. (1) Allotment in the public issue of municipal debt securities should be made on the basis of date of upload of each application into the electronic book of the stock exchange: Provided that on and after the date of oversubscription, the allotments may be made to the applicants on a proportionate basis upto the oversubscription limit.

(2) The issuer and lead manager(s) shall ensure that the municipal debt securities are allotted and/or application monies are refunded or unblocked within such period as may be specified by the Board.

(3) The lead manager(s) shall ensure that the allotment, credit of dematerialised securities and refund or unblocking of application monies, as may be applicable, are done electronically.

(4) Where the securities are not allotted and/or application monies are not refunded or unblocked within the period stipulated in sub-regulation (2) above, the issuer shall undertake to pay interest at the rate of fifteen per cent. per annum to the investors and within such time as disclosed in the offer document and the lead manager(s) shall ensure the same.”

(xv) in regulation 13, the words “revenue bonds” shall be substituted by the words, “municipal debt securities”.

(X) In Chapter IV, in the Chapter heading, the words “**LISTING OF DEBT SECURITIES**”, shall be substituted by the words “**MUNICIPAL DEBT SECURITIES ISSUED ON PRIVATE PLACEMENT BASIS**”.

(XI) In Chapter IV, -

(i) Regulation 14 shall be substituted by the following regulation, namely,-

“Listing on private placement basis

14. An issuer may list its municipal debt securities issued on private placement basis through placement memorandum.”

(ii) Regulation 15 shall be substituted by the following regulations, namely,-

“Preliminary Placement Memorandum

14A (1) Prior to making a private placement of municipal debt securities which are proposed to be listed, the issuer shall file the preliminary placement memorandum with the Board and stock exchange(s) through the merchant banker registered with the Board:

(2) The merchant banker to the issue shall submit the following to the Board along with the preliminary placement memorandum,-

- (a) disclosures as specified in Schedule I and Schedule IA of these regulations; and
- (b) a due diligence certificate as per Form A of Schedule II.

(3) The Board may issue observations, if any, on the preliminary placement memorandum within fifteen days from the later of the following dates:

- a) the date of receipt of the preliminary placement memorandum under sub-regulation (1); or

- b) the date of receipt of satisfactory reply from the issuer and/or merchant banker to the issue, where the Board has sought any clarification or additional information from them; or
- c) the date of receipt of clarification or information from any regulator or agency, where the Board has sought any clarification or information from such regulator or agency; or
- d) the date of receipt of a copy of in-principle approval letter issued by the stock exchange(s).

(4) The merchant banker to the issue, as the case may be, shall ensure that all comments are suitably incorporated in the preliminary placement memorandum prior to filing the placement memorandum to the Stock Exchange(s); and the merchant banker to the issue shall provide the due diligence certificate as specified in Form B and Form C of Schedule II.

(5) The debenture trustee shall, prior to the opening of private placement, furnish to the Board a due diligence certificate as per Schedule III of these regulations.

Minimum subscription.

15. The minimum subscription amount per investor shall be Rupees ten lakh.”

(XII) In Chapter V, -

- (i) regulation 16 shall be substituted by the following regulation, namely,-

“Electronic issuance

16. An issuer proposing to issue municipal debt securities may make the same through the on-line system and shall comply with the relevant requirements as may be specified by the Board.”

- (ii) in regulation 17, after the words “from the investors”, the words “ in the manner as specified by the Board from time to time” shall be inserted.
- (iii) after regulation 17 and before regulation 18, the following regulation shall be inserted, namely,-

“Put or call option

17A. The issuer may recall municipal debt securities prior to maturity date at its option (call) or provide such right of redemption prior to maturity date (put) to all the investors at their option in the manner as may be specified by the Board from time to time:

Provided in all such cases, detailed disclosure shall be made in the offer document or placement memorandum.”

- (iv) in regulation 18, -

- (a) in the heading to the regulation, and in sub-regulation (1), after the words, “offer document”, the words “or placement memorandum”, shall be inserted;
- (b) in sub-regulation (1), after the word “document” and before the words “or placement”, the words, “or term sheet” shall be inserted.
- (c) in sub-regulation (1), after the word “misleading”, the word “in light of the circumstances under which they are made” shall be omitted.
- (d) in sub-regulation (2), the words “abridged prospectus” shall be substituted by the words “term sheet”;
- (e) after the sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely,-

“(3) The offer document or placement memorandum shall contain all material disclosures which are true, correct and adequate to enable the applicants to take an informed investment decision”.

- (v) after regulation 18 and before regulation 19, the following regulations shall be inserted, namely,-

“Utilization of issue proceeds.

18A. (1) The funds raised from issue of municipal debt securities shall be used only for the purposes indicated under the objects stipulated in the offer document or placement memorandum.

(2) Where the proceeds of the issue are earmarked for a defined project or a set of projects, prior requisite approvals, if applicable shall be obtained from the concerned authorities.

(3) The issuers shall maintain a bank account in which the amount raised from the issue shall be immediately transferred after the closure of the issue and such amount shall only be utilised for the indicated project(s):

Provided further that the merchant banker to the issue, in case of private placement, shall confirm to the bankers to the issue by way of copies of listing and trading approvals that all formalities in connection with the issue have been completed and that the banker is free to release the money to the issuer or release the money for refund in case of failure of the issue.

(4) The issuer shall disclose the schedule of implementation of the project in the offer document or placement memorandum in a tabular form and the funds raised by the issuer shall be utilized in accordance with the said Schedule.

Issuer contribution

18B. The contribution of the issuer for each issuance of municipal debt securities shall not be less than twenty per cent. of the project costs, which shall be contributed from their internal resources or grants that may be in cash or kind.”

- (vi) regulation 19 shall be substituted by the following regulation, namely,-

“Creation of Escrow Accounts

19. The issuer shall create a structured payment mechanism and maintain specific escrow accounts for the purpose of debt servicing of the municipal debt securities as specified by the Board from time to time.”

- (vii) regulation 20 shall be substituted by the following regulation, namely,-

“Trust deed.

20. (1) A trust deed for securing the issue of municipal debt securities shall be executed by the issuer in favour of the debenture trustee.

(2) The trust deed shall contain such clauses as may be specified in Schedule IV of the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 1993:

Provided that in case of private placement by a body corporate to which the Companies Act, 2013 applies, the trust deed shall, in-addition contain such clauses as required under section 71 of the Companies Act, 2013 and the Companies (Share Capital and Debentures) Rules 2014.

(3) The trust deed shall not contain a clause which has the effect of:

- (a) limiting or extinguishing the obligations and liabilities of the debenture trustees or the issuer in relation to any rights or interests of the investors;
- (b) limiting or restricting or waiving the provisions of the Act, or Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 or the Depositories Act, 1996, and the regulations and circulars or guidelines issued by the Board from time to time;
- (c) indemnifying the debenture trustees or the issuer for loss or damage caused by their act of negligence or commission or omission.

(4) The issue proceeds shall not be utilised until the Trust deed is executed”

(viii) regulation 21 shall be substituted by the following regulation, namely,-

“Redemption and roll-over.

21. (1) The issuer shall redeem the municipal debt securities in terms of the offer document or placement memorandum.

(2) Where the issuer desires to roll-over the municipal debt securities issued, it shall do so only upon passing of a special resolution to that effect and give twenty one days’ notice of the proposed roll over to the holders of municipal debt securities:

Provided that, if the holders of municipal debt securities do not provide consent for the proposed roll over within the notice period, the issuer shall redeem the municipal debt securities of such holders.

(3) The notice referred to in sub- regulation (2) shall contain disclosures with regard to credit rating and the rationale for roll-over.

(4) The issuer shall, prior to sending the notice to holders of municipal debt securities, file a copy of the notice and proposed resolution with the stock exchanges where such securities are listed, for dissemination of the same to the public on their websites.

(5) The municipal debt securities issued can be rolled over subject to the following conditions:

(a) the roll-over is approved by a special resolution passed by the holders of such municipal debt securities having the consent of not less than 75% of the holders by value of such municipal debt securities:

(b) at least one rating is obtained from a credit rating agency within a period of six months prior to the due date of redemption and is disclosed in the notice referred to in sub-regulation (2);

(c) fresh trust deed shall be executed at the time of such roll over or the existing trust deed may be continued if the trust deed provides for such continuation;

(6) The issuer shall redeem the municipal debt securities of all the holders, who have not given their positive consent to the roll-over.”

(ix) regulation 22 shall be substituted by the following regulations, namely,-

“Face value of municipal debt securities

22. The face value of municipal debt securities shall be disclosed in offer document or placement memorandum in the manner as specified by the Board.

Day count convention

22A. The day count convention for calculation of interest payments for municipal debt securities shall be Actual/Actual and shall be calculated in manner as specified by the Board.

Prohibition on payment of incentives

22B. Any person connected with the issue shall not offer any incentive, whether direct or indirect, in any manner, whether in cash or kind or services or otherwise to any person for making an application in the issue, except for fees or commission for services rendered in relation to the issue.”

(XIII) In Chapter VI, in the Chapter heading, after the word “OF” and before the word “DEBT” the word “MUNICIPAL” shall be inserted.

(XIV) In Chapter VI, -

(i) regulation 23 shall be substituted by the following regulation, namely,-

“Continuous listing conditions.

23. (1) The issuer making public issues of municipal debt securities or seeking listing of municipal debt securities issued on private placement basis, shall comply with the conditions of listing specified in Schedule V of these regulations including continuous disclosure and other requirements specified by the Board from time to time.

(2) Where the issuer is a body corporate to whom the Companies Act, 2013 applies, one-third of its Board shall comprise of independent directors, as defined in section 149 of the Companies Act, 2013.

(3) Any change in rating shall be promptly disseminated in such manner as the stock exchange where such securities are listed may determine from time to time.

(4) The issuer, the respective debenture trustees, and stock exchanges shall disseminate all information and reports regarding municipal debt securities including compliance reports filed by the issuers and the debenture trustees, to the investors and the general public by placing them on their websites.

(5) The information referred to in sub-regulation (3) shall also be placed on the websites of the debenture trustee, the issuer and the stock exchanges.”

(ii) regulation 24 shall be substituted by the following regulation, namely,-

“Accounting and audit.

24. (1) An issuer shall prepare accounts in any of the manner specified in clause (b) of regulation 4:

Provided that in case the Issuer is a body corporate to which the Companies Act, 2013 applies, the accounts shall be prepared in accordance with section 129 and 134 of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder.

(2) In case of the issuer being a municipality, the accounts of the issuer shall be audited by the persons appointed by the municipal corporations, as permissible under its constitution document:

Provided that in case the issuer is a body corporate to which the Companies Act, 2013 applies, the accounts of the issuer shall be audited by an auditor, in terms of section 139 of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder.

(iii) Regulation 25 shall be substituted by the following regulation, namely, -

“Trading and reporting of municipal debt securities.

25. (1) The trades of listed municipal debt securities shall be cleared and settled through a recognised clearing corporation in the manner specified by the Board.

(2) In case of trades in municipal debt securities which have been made over the counter, such trades shall be reported on a recognised stock exchange having a nationwide trading terminal or such other platform as may be specified by the Board from time to time.

(3) The information in respect of issues such as issuer details, instrument details, ratings, rating migration, coupon, buyback etc shall be required to be reported to a common database as may be specified by the Board.”

(XV) In Chapter VII,-

(i) regulation 26 shall be substituted by the following regulation, namely,-

“Obligations of debenture trustee.

26. (1) The debenture trustee shall be vested with the requisite powers for protecting the interest of holders of municipal debt securities:

Provided that, where the issuer is a body corporate to which the Companies Act, 2013 applies such powers shall include a right to appoint a nominee director on the Board of the issuer, in consultation with institutional holders of such securities.

(2) The debenture trustee shall carry out its duties and perform its functions in terms of these regulations, the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 1993, the trust deed and the offer document/placement memorandum, with due care, diligence and loyalty.

(3) The debenture trustee shall monitor the separate escrow account maintained in respect of the earmarked revenue.

(4) The debenture trustee shall ensure disclosure of all material events on an ongoing basis.

(5) The debenture trustee shall supervise the implementation of the obligations cast in terms of provisions of these regulations.”

(ii) in regulation 27, shall be substituted by the following, namely, -

“Obligations of the issuer and merchant banker.

27. (1) The issuer shall disclose all the material facts in the offer documents issued or distributed to the public and shall ensure that all the disclosures made in the offer document are true, fair and adequate and there is no mis-leading or untrue statements or mis-statement in the offer document.

(2) The merchant banker(s) shall verify and confirm that the disclosures made in the offer documents are true, fair and adequate and ensure that the issuer is in compliance with these regulations.

(3) The merchant banker(s) shall ensure that all transaction specific disclosures required in Schedule I of these regulations are complied with:

Provided that where the issuer is a body corporate to which the Companies Act, 2013 applies, the merchant banker(s) shall also ensure that the disclosures under Companies Act, 2013 and rules made thereunder are complied with.

(4) The issuer shall treat the applicants in a public issue of municipal debt securities in a fair and equitable manner as per the procedures as may be specified by the Board.

(5) The merchant bankers shall be responsible for the due diligence in respect of assignments undertaken by them in respect of issue, offer and distribution of securities to the public.

(6) There shall be no conflict of interest between the lead manager(s) and the issuer or its group companies in accordance with the applicable regulations.”

(XVI) after Chapter VII and before Chapter VIII, the following Chapter shall be inserted, namely,-

**“CHAPTER VIIA
PROCEDURE IN CASE OF VIOLATION OF REGULATIONS**

Directions by the Board

27A. Without prejudice to the action under section 11, 11A, 11 B, 11D, sub- section (3) of section 12, Chapter VIA and section 24 of the Act or section 439 of the Companies Act, 2013, the Board may *suo-motu* or upon receipt of information or on completion or pendency of

inspection or investigation, in the interests of the securities market, issue or pass such directions as it deems fit including any or all of the following:

- (a) direct the issuer to refund the application monies to the applicants in a public issue;
- (b) direct the persons concerned not to further deal in securities in any particular manner;
- (c) direct the persons concerned not to access the securities market for a specified period;
- (d) restrain the issuer or its promoters or directors from making further issues of securities;
- (e) direct the person concerned to sell or divest the securities;
- (f) direct the issuer or the depository not to give effect transfer or directing further freeze of transfer of securities;
- (g) any other direction which Board may deem fit and proper in the circumstances of the case:

Provided that the Board shall, either before or after issuing such directions, give an opportunity of being heard to the persons against whom the directions are issued or proposed to be issued:

Provided further that if any ex-parte direction is required to be urgent issued, the Board may give post decisional hearing to the affected person:

Provided also that where the issuer is a Municipality, the Board may communicate the instances of violation or non-compliance etc. if any, to the Central Government and the concerned State Government.”

(XVII) Regulation 28 shall be omitted;

(XVIII) In Chapter VIII, after regulation 29, the following regulations shall be inserted, namely, -

“Power to relax strict enforcement of Regulations

30. The Board may, in the interest of investors or for the development of the securities market, relax the strict enforcement of any requirement of these regulations, if the Board is satisfied that, -

- (a) the requirement is procedural or technical in nature; or
- (b) the requirement may cause undue hardship to investors; or
- (c) the disclosure requirement is not relevant for a particular industry or class of issuers; or
- (d) the non-compliance was caused due to factors beyond the control of the issuer ;or
- (e) such relaxation will be in the interest of securities market.”

(XIX) Schedule I shall be substituted by the following Schedule, namely-

“SCHEDULE I

[See regulations 6 and 27]

**DISCLOSURES IN THE OFFER DOCUMENT AND PLACEMENT
MEMORANDUM**

All disclosures specified under this schedule shall be made in the draft offer document or the preliminary placement memorandum or offer document or placement memorandum, as applicable.

1. Instructions:

- (a) All information shall be relevant and updated. The source and basis of all statements and claims shall be disclosed.
- (b) All blank spaces in the draft offer document/ preliminary placement memorandum shall be filled up with appropriate data before registering the offer document /placement memorandum, as applicable, with the Registrar of Companies or filing the same with the recognised stock exchanges.

- (c) Plain English shall be used to enable easy understanding of the contents. Technical terms, if any, used in explaining the business of the issuer shall be clarified in simple terms.
- (d) Wherever it is mentioned that details are given elsewhere in the document, the same shall be adequately cross-referenced by indicating the paragraph heading and page number.
- (e) There shall be no forward-looking statements that cannot be substantiated.
- (f) Consistency shall be ensured in the style of disclosures. If the first person is used, the same may be used throughout. All sentences that contain a combination of first and third persons may be avoided.
- (g) For presentation currency, only one standard financial unit shall be used.

2. Applicability:

An issuer making a public issue or private placement of municipal debt securities that are intended to be listed shall make the disclosures as specified in this Schedule.

3. General information:

- (a) Name and address of the head office and other offices of the issuers
- (b) Registered and corporate office of the issuer, if applicable
- (c) Details of Mayor / Deputy Mayor including date of appointment, etc.
- (d) Details of Commissioner/ Deputy Commissioner including date of appointment, etc.
- (e) Details of the members of the Committee approving the project/ various Standing Committees relating to Taxation / Finance /Accounts/ Audit/ Infrastructure in the following format :-

Name and Designation	Date of Appointment or Resignation	Member of the Committee since (in case of resignation)	Remarks

- (f) Name, designation, address and DIN of each member of the board of directors of the issuer if the issuer is a company.
- (g) Name, address, telephone number and email address of the compliance officer of the issuer
- (h) Complete Details of the Official In-charge of dealing with investor Grievances related to the Municipal Bonds, his/her address, phone number, email ID, etc.
- (i) Chief Accounts and Finance Officer or equivalent of the Issuer
- (j) Arrangers, if any, of the instrument
- (k) Debenture trustee of the issue
- (l) Registrar to an issue
- (m) Credit Rating Agency (-ies) of the issue and
- (n) Auditors of the Issuer
- (o) Names, addresses, telephone numbers, contact person, website addresses and e-mail addresses of the lead manager(s), registrars to the issue, bankers to the issue, brokers to the issue and syndicate member(s); alongwith URL of SEBI website listing out the details of self-certified syndicate banks, registrar to the issue and depository participants, etc., if applicable.
- (p) Names, addresses, telephone numbers and e-mail addresses of the Company Secretary, legal advisor, underwriters and bankers to the issuer.
- (q) Names of the debenture trustee(s) shall be mentioned with a statement to the effect that the debenture trustee(s) has given his consent to the Issuer for his appointment. This also needs to be mentioned in all subsequent communications sent to the holders of debt securities.
- (r) Investor grievances redressal mechanisms

4. About the issuer and Capital structure of the issuer:

- (a) The constitution document

- (b) Details of the capital structure of the issuer, if applicable.
- (c) Details of the management structure of the issuer.
- (d) Shareholding pattern of the issuer along with top 10 shareholders of the issuer, if applicable.
- (e) Resolution authorizing the borrowing and list of authorized signatories.
- (f) Details of necessary Resolution(s) for the allotment of municipal debt securities
- (g) Memorandum and Articles of Association in case the issuer is a body corporate incorporated under Companies Act, 2013, if applicable
- (h) Details of any Reorganization or Reconstruction of management in the last 1 year of the issuer.
- (i) Details of all the project undertaken or proposed in terms of cost and means of financing
- (j) Capital structure relating to projects for which funds are proposed to be mobilized
- (k) Capital grant for the proposed project and the amount received in this regard
- (l) Details of State Finance Commission Grant on annual basis

5. **Objects of the issue:**

- (a) The proceeds of the proposed issue shall be clearly earmarked for a defined project or a set of projects along with the location of the project and plant and machinery, technology, process, etc.;
- (b) Where the issuer proposes to undertake more than one activity or project, such as diversification, modernization, or expansion, etc., the total project cost activity-wise or project wise, as the case may be.
- (c) Where the issuer is implementing the project in a phased manner, the cost of each phase, including the phase, if any, which has already been implemented, shall be separately given.
- (d) An investment plan for the project components as well as phases thereof as well as financing thereof as approved by the local authority or the agency as the case may be
- (e) Schedule of implementation of the project
- (f) Benchmarks for commencement and completion of the project including milestone dates for all components of the project
- (g) Details and status of the regulatory approval (if required)
- (h) Expenses of the Issue:

Expenses of the issue along with a break up for each item of expense, including details of the fees payable to/for separately as under (in terms of amount, as a percentage of total issue expenses and as a percentage of total issue size):

- (a) Lead manager(s) fees including underwriting commission
- (b) Brokerage, selling commission and upload fees
- (c) Registrars to the issue
- (d) Legal Advisors
- (e) Advertising and marketing expenses
- (f) Regulators including stock exchanges
- (g) Printing and distribution of issue stationary
- (h) Others, if any (to be specified).

6. **Tax Benefits:**

Any special tax benefits (under direct and indirect tax laws) for the issuer and its investors

7. **Issue specific Information:**

- (a) Issue/instrument specific regulations - relevant details (Relevant Act, RBI guidelines, etc.).
- (b) The detailed rating rationale (s) adopted (not older than one year on the date of opening of the issue)/ credit rating letter issued (not older than one month on the date of opening of the issue) by the rating agencies shall be disclosed. Names of all the credit

rating agencies from which credit rating including unaccepted rating has been obtained.

- (c) Credit Enhancement Mechanisms if any, with complete details, if any.
- (d) Names of all the recognised stock exchanges where the debt securities are proposed to be listed clearly indicating the designated stock exchange.
- (e) Additional interest to be paid, above the Coupon Rate, in case of default in payment of Interest and/or principal redemption on the due dates
- (f) Penal interest payable by the issuer in case of delay in listing of debt securities from the deemed date of allotment
- (g) Debenture Redemption Reserve and such other reserve creation - relevant regulations as applicable.
- (h) Application process
- (i) Procedure for deciding and adjusting payment dates (in response to days when payment cannot be made due to any reason such as sudden bank holiday.
- (j) 'Terms of payments' and procedure and time schedule for allotment and issue certificates/demat credit
- (k) How to apply, availability of application forms and letter of offer and mode of payment.
- (l) Change in terms and conditions of municipal debt securities issued in past 5 years (i.e. change in coupon, maturity, call/put option etc.)
- (m) Procedure and time schedule for allotment and issue of municipal debt securities.
- (n) Details of escrow payment mechanism for the repayment of the interest/principal.

8. Financial Information:

I. Following details as per the financial statements for past 3 years in tabular format:

- (a) Abridged Balance Sheet, Income and Expenditure and Receipts and Payments Accounts for the last three financial years with major heads
- (b) Link to the web page where the entire financials of the Municipal Body can be accessed should be given.
- (c) Copy of budget documents for the previous three years containing actual financial performance and/or revised estimates along with the details of related party transactions
- (d) Financial Parameters:

Key Financial Figures	FY	FY	FY
Revenue income			
Revenue expenditure (Excl. Interest)			
Operating revenue Surplus			
Interest expense			
Principal repayment (outside sinking Fund)			
Contribution to Sinking fund			
Revenue surplus			
Capital income			
Capital expense			
Capital surplus			
Overall surplus			
Deposits and Advances (net)			
Initial Cash / Bank balance			
Change in Cash /			

Bank balance			
Final Cash / Bank balance			
Loan repayment from sinking fund			
Initial Sinking fund balance			
Change in sinking fund			
Final sinking fund balance			
Total debt			
Ratio of Total Expenditure / Total Revenue			
Cash surplus / total revenue			
Ratio of Debt Service / Total Revenue			

II. Details of top five revenue sources for the previous three years

Revenue Receipt type	Actual	Actual	Actual
	FY	FY	FY
XYZ 1			
XYZ 2			
XYZ 3			
XYZ 4			
XYZ 5			

III. Details of property tax collection

Particulars		Demand Raised		Collections		Overall Collection ratio	Current Collection ratio		
	Arrears		Current	Total	Current	Arrear	Total		
FY									
FY									
FY									

IV. Status of reforms with respect to e-governance, cost recovery on water supply, Solid Waste Management (SWM), property tax, double entry accounting and others, as specified by Central Government and authorities concerned

V. Borrowings

(a) Details of borrowings of the Issuer, as on the latest quarter end:-

(b) Details of Secured Loan Facilities:-

Lender's Name	Type of Facility	Amt Sanctioned	Principal Amt outstanding	Repayment Date / Schedule	Security

(c) Details of Unsecured Loan Facilities:-

Lender's Name	Type of Facility	Amt Sanctioned	Principal Amt outstanding	Repayment Date / Schedule

(d) Details of NCDs/Bonds: -

Debenture/ Bond Series	Tenor/ Period of Maturity	Coupon	Amount	Date of Allotment	Redemption Date/ Schedule	Credit Rating	Secured/ Unsecured	Security

(e) List of the Top ten Debenture Holders (as on)

Sr. No.	Name of Debenture Holders	Amount

Note: Top ten holders' (in value terms, on cumulative basis for all outstanding debentures issues) details should be provided.

(f) Details of Commercial Paper:- The total Face Value of Commercial Papers Outstanding as on the latest quarter end to be provided and its breakup in following table:-

Maturity Date	Amount Outstanding

(g) Details of Rest of Borrowings

(h) Details of any outstanding borrowings and debt securities issued for consideration other than cash, whether in whole or part, at a premium or discount, or in pursuance of an option;

VI. Sufficient revenue generation and resources for timely servicing and redemption

VII. Estimated Scenarios of Asset Liability Mis-matches, efforts intended to resolve the same.

9. Legal and Other Information:

(a) Pending litigations and material developments:

Pending Litigations involving the issuer/ its directors/ promoters/ subsidiaries:

(i) All criminal proceedings;

- (ii) All actions by regulatory and statutory authorities;
 - (iii) Disciplinary action including penalty imposed by SEBI or stock exchanges against the promoters during the previous five financial years including outstanding action;
 - (iv) Claims related to direct and indirect taxes, in a consolidated manner, giving the number of cases and total amount;
 - (v) Other pending litigation - As per the policy of materiality defined by the Board of Directors of the Issuer and disclosed in the offer document/placement memorandum.
- (b) Outstanding dues to creditors:
- (i) Based on the policy on materiality defined by the Board of Directors of the Issuer, details of creditors which include the consolidated number of creditors and the aggregate amount involved
 - (ii) Consolidated information on outstanding dues to micro, small and medium enterprises, separately giving details of number of cases and amount involved;
 - (iii) Complete details about outstanding dues to material creditors along with the name and amount involved for each such material creditor shall be disclosed, on the website of the company with a web link thereto.
- (c) If any of the above mentioned litigation, material developments or dues to creditors etc., arise after the filing the draft offer document/ preliminary placement memorandum, the facts shall be appropriately incorporated in the offer document/placement memorandum. In case there are no such cases, a distinct negative statement is required to be made in this regard in the offer document/ placement memorandum.
- (d) Material developments since the date of the last balance sheet shall be incorporated separately in the offer document or placement memorandum.
- (e) Statement containing particulars of dates of, and parties to all material contracts and agreements:
Provided that a recognized stock exchange may call for such further particulars or documents as it deems appropriate
- (f) Any material event/ development or change having implications on the financials/credit quality (e.g. any material regulatory proceedings against the Issuer, resulting in material liabilities, restructuring event etc) at the time of the issue which may affect the issue or the investor's decision to invest/ continue to invest in the municipal debt securities.
- (g) Details of non-payment of statutory dues, if any.
- (h) Details of all default/s and/or delay in payments of interest and principal of any kind of term loans, debt securities and other financial instrument issued by the Issuer, in the past 3 years.

10. Government approvals:

- (a) Investment approvals, letter of intent or industrial license from GoI, RBI, etc., as applicable and declaration of the Central Government, Reserve Bank of India or any regulatory authority about the non-responsibility for financial soundness or correctness of the statements;
- (b) All Government and other approvals which are material and necessary for carrying on the business and operations of the issuer and material subsidiaries.

11. Undertaking by the issuer:

The following undertaking by the issuer shall be given:

- (a) that it shall submit the documents disclosed in the offer document or placement memorandum to the Debenture Trustee in electronic form (soft copy)

- (b) that the complaints received in respect of the issue shall be attended to by the issuer expeditiously and satisfactorily;
- (c) that all steps for completion of the necessary formalities for listing and commencement of trading at all stock exchanges where the securities are to be listed are taken within the period specified by the Board;
- (d) Declaration signed by the Mayor and Commissioner of the concerned Municipal Body stating that the offer document/placement memorandum contains true, fair and adequate information to enable investors to make a well informed decision regarding their investment in the proposed issue.
- (e) Declaration signed by the Director(s) of the Issuer, if it is a body corporate to which the Companies Act, 2013 applies, stating that offer document/placement memorandum contains true, fair and adequate information to enable investors to make a well informed decision making regarding their investment in the proposed issue.
- (f) a statement to be given by the Board of the Issuer or Standing Committee thereof that all monies received out of the issue shall be transferred to a separate bank account.
- (g) the details of all utilized and unutilised monies out of the monies collected in the previous issue made by way of public offer shall be disclosed and continued to be disclosed in the balance sheet till the time any part of the proceeds of such previous issue remains unutilized indicating the purpose for which such monies have been utilized and the securities or other forms of financial assets in which such unutilized monies have been invested

12. Documents to be submitted

- (a) Copy of the resolution authorizing the borrowing and list of authorized signatories.
- (b) Copy of the Trust deed.
- (c) Documents that have been executed or shall be executed in relation to the issue

13. Risk factors:

- (a) Risk factors shall be printed in a clear readable font (of minimum point ten size).
- (b) Risk factors shall be classified as those which are specific to the project and internal to the issuer and those which are external and beyond the control of the issuer.
- (c) Risk factors shall be determined on the basis of their materiality. In doing so, the following shall be considered:
 - i. Some risks may not be material individually but may be material when considered collectively.
 - ii. Some risks may have an impact which is qualitative though not quantitative.
 - iii. Some risks may not be material at present but may have a material impact in the future.
- (d) Each risk factor shall appear in the following manner:
 - i. The risk as envisaged by the issuer.
 - ii. Proposals, if any, to address the risk.
- (e) Comprehensive Disclosure regarding the Risk Factors, including project risks, operational risks, credit risks, liquidity risks, etc.
- (f) Management perception of risk factors specific to the project.

14. Such other details necessary for the investors to make a well informed decision making regarding their investment in the proposed issue.”

(XX) After Schedule I and before Schedule II, the following Schedule shall be inserted, namely,-

“Schedule IA
[See regulations 6 and 14A]

TERM SHEET

Summary of Offer

This section shall contain the summary of the following information, as applicable:

- (a) Primary business of the issuer, in not more than 100 words each;
- (b) Size of the issue;
- (c) Objects of the issue in a tabular format;
- (d) Audit qualifications along with the financial statements, if any
- (e) Summary table of pending litigation and a cross-reference to the section titled '*Pending Litigation and Material Developments*'.
- (f) Cross-reference to the section titled '*Risk Factors*'
- (g) Summary table of contingent liabilities and a cross-reference to contingent liabilities of the issuer as disclosed in the restated financial statements.
- (h) Summary of related party transactions for the previous three years and cross-reference to related party transactions as disclosed in financial statements.
- (i) Details of escrow payment mechanism for the repayment of the interest/principal.

Summary term sheet shall be provided which shall include following information (where relevant) pertaining to the issue of municipal debt securities (or a series thereof) and any other substantial information deemed relevant:-

Security name	
Issuer	
Type of instrument	
Seniority	
Mode of issue	
Eligible investors	
Listing (including name of the stock exchange(s) where it would be listed and the timeline for listing)	
Rating of the instrument	
Issue size	
Option to retain oversubscription (amount)	
Objects of the issue	
Details of the utilization of the proceeds	
Coupon rate	
Taxable/tax free	
Step up/step down coupon rate	
Coupon payment frequency	
Coupon payment dates	
Coupon type	
Coupon reset process (including rates, spread, effective date, interest rate cap and floor etc).	
Day count basis	

Interest on application money	
Tenor	
Redemption date	
Redemption amount	
Redemption premium /discount	
Issue price	
Discount at which the security is issued and the effective yield as a result of such discount.	
Put option date	
Put option price	
Call option date	
Call option price	
Put notification time	
Call notification time	
Face value	
Minimum application for municipal debt securities or multiples thereof	
Issue timing 1. Issue opening date 2. Issue closing date 3. Pay-in date 4. Deemed date of allotment	
Issuance mode of the instrument	
Trading mode of the instrument	
Settlement mode of the instrument	
Depository	
Business day convention	
Record date	
Transaction documents	
Conditions precedent to disbursement	
Condition subsequent to disbursement	
Events of default	
Provisions related to cross default clause	
Role and responsibilities of debenture trustee	
Governing law and jurisdiction	

”

(XXI) Schedule II shall be substituted by the following Schedule, namely,-

“SCHEDULE II
[See regulations 7 and 14]

Form A

FORMAT OF DUE DILIGENCE CERTIFICATE TO BE GIVEN BY THE LEAD MANAGER (S)/MERCHANT BANKER ALONG WITH DRAFT OFFER DOCUMENT/ PRELIMINARY PLACEMENT MEMORANDUM

To,
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

Dear Sirs,

SUB.: ISSUE OF _____ BY _____ (Issuer)

We CONFIRM that:

- (1) We have examined documents pertaining to the said issue and other relevant documents.
- (2) On the basis of such examination and discussions with the Issuer, its directors and other officers, other agencies, and independent verification of the statements concerning the objects of the issue, contents of the documents and other papers furnished by the issuer:
 - (a) the draft offer document/ preliminary placement memorandum filed with the Board is in conformity with the documents, materials and papers which are material to the issue;
 - (b) all material legal requirements relating to the issue as specified by the Board, the Central Government and any other competent authority in this behalf have been duly complied with; and
 - (c) the material disclosures made in the draft offer document/preliminary placement memorandum are true and adequate to enable the investors to make a well informed decision as to the investment in the proposed issue and such disclosures are in accordance with the requirements of the Companies Act, 2013, these regulations and other applicable legal requirements.
- (3) All intermediaries named in the draft offer document/ preliminary placement memorandum are registered with the Board and that till date, such registration is valid and that none of these intermediaries have been debarred from functioning by any regulatory authority.
- (4) Necessary arrangements shall be made to ensure that the monies received pursuant to the issue are credited or transferred to in a separate bank account.
- (5) We shall comply with the provisions pertaining to advertisements in terms of the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Municipal Debt Securities) Regulations, 2015.
- (6) The offer document or placement memorandum registered with the Registrar of Companies and filed with the designated stock exchange on (date) was suitably updated under intimation to the Board and that the said offer document or placement memorandum contains all the material disclosures in respect of the issuer as on the said date.
- (7) Agreements have been entered into with the depositories for dematerialisation of the securities of the issuer.

We enclose a note explaining the process of due diligence that has been exercised by us for the period disclosed in the draft offer document/preliminary placement memorandum in accordance with applicable laws.

We enclose a checklist confirming regulation-wise compliance with the applicable provisions of these regulations, containing details such as the regulation number, its text, the status of compliance, page number of the draft offer document/ preliminary placement memorandum where the regulation has been complied with and our comments, if any.

PLACE:
DATE:

(SIGNATURE WITH OFFICIAL SEAL)
LEAD MANAGER/
MERCHANT BANKER

Form B**FORMAT FOR DUE DILIGENCE CERTIFICATE AT THE TIME OF FILING THE OFFER DOCUMENT OR PLACEMENT MEMORANDUM BY LEAD MANAGER/MERCHANT BANKER PRIOR TO THE OPENING OF THE ISSUE**

To,

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

Dear Sir / Madam,

SUB.: ISSUE OF _____ BY _____

1. We CONFIRM that neither the issuer nor its promoters or directors or other officers have been prohibited from accessing the capital market under any order or direction passed by the Board. We also confirm that none of the intermediaries named in the offer document or placement memorandum have been debarred from functioning by any regulatory authority.

2. We CONFIRM that all the material disclosures in respect of the issuer have been made in the offer document and certify that any material development relating to the issue up to the commencement of listing and trading of the municipal debt securities offered through this issue shall be informed through public notices/ advertisements in all those newspapers in which pre-issue advertisement and advertisement for opening or closure of the issue have been given.

3. We CONFIRM that the offer document or placement memorandum contains all disclosures as specified in the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Municipal Debt Securities) Regulations, 2015.

4. We CONFIRM that all relevant provisions of the Companies Act, 2013, if applicable, Securities Contracts, (Regulation) Act, 1956, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and the Rules, Regulations, Guidelines, Circulars issued thereunder have been complied with.

5. We CONFIRM that all comments/ complaints received on the draft offer document/ preliminary placement memorandum filed with the _____ (designated stock exchange) have been suitably addressed.

PLACE: (SIGNATURE WITH OFFICIAL SEAL)

**DATE: LEAD MANAGER /
MERCHANT BANKER**

Form C**FORMAT OF DUE DILIGENCE CERTIFICATE TO BE GIVEN IN THE EVENT OF DISCLOSURE OF MATERIAL EVENTS AFTER THE FILING OF THE OFFER DOCUMENT/PLACEMENT MEMORANDUM BY THE LEAD MANAGER(S)/MERCHANT BANKER(S)**

To,

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

Dear Sirs,

SUB.: ISSUE OF _____ BY _____ (Issuer)

We CONFIRM that all material disclosures in respect of the issue as on date have been made through the offer document or placement memorandum registered with the Registrar of Companies and filed with the designated stock exchange on (date).

PLACE: (SIGNATURE WITH OFFICIAL SEAL)
DATE: LEAD MANAGER/
 MERCHANT BANKER

(XXII) Schedule III shall be substituted by the following Schedule, namely, -

“SCHEDULE III
[See regulations 7 and 14]

FORMAT OF DUE DILIGENCE CERTIFICATE TO BE GIVEN BY THE DEBENTURE TRUSTEE BEFORE OPENING OF THE ISSUE

To,
 SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
 Dear Sir / Madam,

SUB.: ISSUE OF _____ BY _____ (Issuer)

We, the Debenture Trustee (s) to the above mentioned forthcoming issue state as follows:

- (1) We have examined documents pertaining to the said issue and other relevant documents.
- (2) On the basis of such examination and discussions with the issuer, its Mayor/Deputy Mayor/Directors and other officers, other agencies and independent verification of the various relevant documents,-
 - (a) WE CONFIRM that the issuer has made adequate provisions regarding escrow payment mechanism for repayment of debt obligations, and
 - (b) We have satisfied ourselves about the ability of the issuer to service the debt securities.

PLACE: (SIGNATURE WITH OFFICIAL SEAL)
DATE: DEBENTURE TRUSTEE TO THE ISSUE”

(XXIII) In Schedule IV, the words and symbols, “_____ Municipal Corporation or _____ Ltd (or Corporate Municipal Entity)” shall be substituted by the following words and symbols, namely,-

“_____ Municipality or _____ Name of the Issuer”

(XXIV) Schedule V, shall be replaced by the following Schedule, namely, -

“SCHEDULE V
[See sub-regulation (1) of regulation 23]
Periodic Disclosures to be made by Issuers

- i. Material adverse changes affecting ability to service bonds.
- ii. Proposal for pre-payment, valuation of bond in case of sale/purchase before maturity, etc.
- iii. Important ratios like debt equity ratio, debt service coverage ratio, interest service coverage ratio, etc.

- iv. Half yearly return on servicing of bonds, credit enhancement facilities and investors grievances and redressal.”

[ADVT.-III/4/Exty./229/19]

AJAY TYAGI, CHAIRMAN

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities by Municipalities) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on July 15, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/006.
2. The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities by Municipalities) Regulations, 2015 were subsequently amended on, -
 - (1) February 15, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities by Municipalities) (Amendment) Regulations, 2017 published in the Official Gazette vide Notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/032.